घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 235- शुक्रवार 26- जून 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

वेनेजुएला में 39 सेकेंड में भूकंप के 2 बड़े झटके,60 सेकेंड तक हिलता रहा शहर

10 हजार से अधिक लोगों की मौत,कई घायल

सर्वे में 44 % आशंका 10,000 मरे...30 % बोले...एक लाख से ज्यादा ने गवाई जान...

वेनेजुएला,25 जून 2026। वेनेजुएला में 39 सेकेंड के अंदर दो ताकतवर भूकंप से तबाही मच गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम 6.04 बजे 7.2 और 6.05 बजे 7.5 तीव्रता के दो झटके आए। उस समय भारत में गुरुवार तड़के 3.34 और 3.35 बजे थे। अगले 60 सेकेंड तक 20 ऑफ्टरशॉक भी दर्ज किए गए हैं। अब तक 164 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 971 घायल हैं। ये भूकंप ऐसे दिन आए, जब पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश था। 1821 में स्पेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई की ऐतिहासिक जीत की सालगिरह पर स्कूल और दफ्तर बंद थे। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने घरों में मौजूद थे। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक, भूकंप से 10 हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने की 44% आशंका है। वहीं, 30% आशंका एक लाख लोगों के जान गंवाने की भी है। दोनों भूकंप राजधानी कराकस से करीब 290 किलोमीटर पश्चिम में आए। इससे कई शहरों में इमारतें गिर गईं या खतरनाक तरीके से झुक गईं। कराकस एयरपोर्ट की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। इससे धूल का गुबार उठता दिखाई दिया।भारी जनहानि की आशंका अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इस आपदा को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। एजेंसी के मुताबिक, यह वेनेजुएला में पिछले 126 वर्षों में आया सबसे बड़ा भूकंप है। आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर स्त्रस ने अनुमान लगाया है कि इस त्रासदी में 10,000 से अधिक लोगों की जान जाने की संभावना 44% तक है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने 1 लाख से अधिक मौतों की आशंका को भी 30% तक बताया है, जो इस आपदा की भयावहता को दर्शाता है। इससे पहले वर्ष 1900 में देश ने 7.7 तीव्रता का भूकंप झेला था। । वेनेजुएला की इस त्रासदी के साथ ही दुनिया के दूसरे छोर, जापान में भी 6.9 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार, केवल दो घंटों के भीतर दुनिया के दो अलग-अलग हिस्सों में ऐसे बड़े भूकंप आना एक बेहद दुर्लभ घटना है, जो लगभग 1,000 से 1,200 साल में एक बार देखने को मिलती है।

मलबे में तब्दील हुई इमारतें...

राजधानी कराकास में भूकंप के प्रभाव से कई बहुमंजिला इमारतें जमींदोज हो गई हैं। विशेष रूप से शहर के पूर्वी इलाके चाकाओ में दो बड़ी इमारतें गिरने की खबर है, जहां स्थानीय प्रशासन के अनुसार कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। कराकास एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा भी गिर गया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। गृह मंत्री डिओसदादो कावेलो ने जानकारी दी है कि फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मलबे से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तैनात कर दी गई हैं। अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सोमवार तक के लिए सभी शैक्षणिक व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।

प्रेसिडेंट की अपील...लापता लोगों...टूटे घरों की जानकारी वेनएप पर दें...

वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने लोगों से अपील की है कि लापता लोगों और टूटे घरों की जानकारी वेनएप पर दें। वेनेजुएला का वेनएप थोड़ा विवादित रहा है। यह पहले सामाजिक और राजनीतिक रूप से नियंत्रण रखने के रूप में इस्तेमाल होता था। वेनएप 2022 में लोगों की शिकायतों के मकसद से लॉन्च किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने 2024 में इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी आंदोलनों की जानकारी लेने में किया। इसके बाद एप को गूगल प्ले स्टोर और एपल आईओएस ने हटा दिया था।

दक्षिण अमेरिका के 8 देश मदद के लिए आगे आए...

दक्षिण अमेरिका के 8 देशों ने वेनेजुएला हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, बोलीविया, कोस्टा रिका और एल सल्वाडोर ने संवेदना व्यक्त करते हुए राहत और बचाव कार्य में सहयोग की पेशकश की है। इन देशों की सरकारों ने अलग-अलग बयान जारी कर भूकंप में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर वे राहत सामग्री, मानवीय सहायता और रेस्क्यू टीम उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने जान गंवाने वालों के प्रति जताया शोक

वेनेजुएला की राजधानी काराकास में दो शक्तिशाली भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें भारी जानमाल की हानि हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को इस तबाही में जान गंवाने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, वेनेजुएला में आए भीषण भूकंपों से हुई तबाही से मैं बेहद दुखी हूं। भारत की जनता की ओर से,वे वेनेजुएला सरकार और जनता,विशेषकर उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं तथा इस मुश्किल समय में सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है।'' उल्लेखनीय है कि काराकास में दो शक्तिशाली भूकंप आने से भारी तबाही हुई है और कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई है।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेजन के सीईओ जेसी,भारत में 13 अरब डॉलर के अतिरिक्त निवेश का किया ऐलान

नई दिल्ली,25 जून 2026। दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स और आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) कंपनी अमेजन ने 2030 तक भारत में कृत्रिम मेधा (एआई) एवं क्लाउड अवसंरचना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 13 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना का एलान किया है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एंडी जेसी ने गुरुवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें ई-कॉमर्स कंपनी की 2030 तक भारत में कृत्रिम मेधा (एआई) एवं क्लाउड अवसंरचना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 13 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना के बारे अवगत कराया। एंडी जेसी ने 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में भारत के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई। जेसी ने लिखा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ भारत में अमेजन के भविष्य को लेकर हुई बैठक में मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि इस नए निवेश से 2026 से 2030 के बीच भारत में अमेजन का कुल पूंजी निवेश 48 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। अमेजन के सीईओ ने आगे कहा कि हम एक दशक से ज्यादा समय से भारत में ग्राहकों, सेलर्स, डेवलपर्स, स्टार्टअप्स और कंपनियों की सेवा कर रहे हैं और अभी तो बस शुरुआत ही हुई है। मैंने बताया कि हम अगले पांच सालों में 48 अरब डॉलर का निवेश कर रहे हैं, जिसमें एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 21 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश शामिल है। एंडी जेसी ने कहा कि 2023 तक हमारी योजना 38 लाख (3.8 मिलियन) नौकरियों को सपोर्ट करने, 80 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने और 1.5 करोड़ (15 मिलियन) छोटे व्यवसायों और 40 लाख (4 मिलियन) सरकारी स्कूल के छात्रों तक एआई के फायदे पहुंचाने की है।

भाजपा की नई टीम घोषित,राजनाथ सिंह के बेटे बने प्रदेश उपाध्यक्ष

लखनऊ,25 जून 2026। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई संगठनात्मक टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 46 पदाधिकारियों की सूची जारी की है। नई टीम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना और विभिन्न सामाजिक व जातीय समीकरणों को साधना है। नई टीम में सबसे चर्चित नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह का है, जिन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले यह पद उनके बड़े भाई और नोएडा से विधायक पंकज सिंह के पास था। पार्टी ने इस बदलाव के जरिए संगठन में नई ऊर्जा और नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। राजनीतिक हलकों में इसे भाजपा की नई रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी से राजनीति में पहचान बनाने वाली पूजा पाल को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। पूजा पाल का पार्टी संगठन में शामिल होना भाजपा के सामाजिक विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं बाराबंकी की पूर्व सांसद प्रियंका रावत को पदोन्नति देते हुए महामंत्री से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव और सक्रिय भूमिका को देखते हुए यह जिम्मेदारी सौंपी है। नई सूची में संजय राय और विधायक राजेश चौधरी को प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया गया है। दोनों नेताओं को संगठनात्मक कार्यों और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा का मानना है कि इन नेताओं के अनुभव से संगठन को आगामी चुनावों में मजबूती मिलेगी। युवाओं को संगठन से जोड़ने के उद्देश्य से रोहित मिश्रा को भाजपा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी नेतृत्व का विश्वास है कि रोहित मिश्रा युवाओं के बीच भाजपा की पहुंच को और मजबूत करेंगे तथा युवा मतदाताओं को संगठन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए यह नियुक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा की नई टीम सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और चुनावी गणित को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट ने एफआईआर कराई

अयोध्या,25 जून 2026। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें 8 आरोपी बनाए गए हैं। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। एसआईटी जांच के लिए 13 जून को बनाई गई थी। 23 जून को इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। एफआईआर में ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव (टिन्नू), लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडेय के नाम हैं।

राम मंदिर विवाद...सांसद संजय सिंह ने एसआईटी को सौंपे 11 सबूत,बोले-महाघोटाला हुआ

अयोध्या,25 जून 2026। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे और दान में गड़बड़ी की जांच एसआईटी कर रही है। आज आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईटी के सामने पेश हुए। उन्होंने राम मंदिर में जमीन घोटाले से जुड़े 11 दस्तावेज एसआईटी को सौंपे। करीब 15 मिनट तक संजय ने एसआईटी के प्रमुख विजय विश्वास पंत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीन खरीद में बड़ा घोटाला हुआ है और इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संजय ने कहा,एक-एक कर सब सामने आ रहा है। पैसे की बरामदगी हो चुकी है,चढ़ावे में चोरी के तमाम सबूत मिल चुके हैं। फिर भी अब तक कोई जेल क्यों नहीं गया? किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोई एफआईआर अब तक क्यों दर्ज नहीं हुई?

नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने सिलेबस में इमरजेंसी 1975-77 जोड़ा,कक्षा 9 वीं के छात्रों को पढ़ाया जाएगा

नई दिल्ली,25 जून 2026। शैक्षणिक जगत में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने पहली बार कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में 1975-77 के आपातकाल (इमरजेंसी) के दौर को शामिल किया है। नई किताब, जिसका शीर्षक 'अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड' है, इसमें इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। एनसीईआरटी के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस संवेदनशील और ऐतिहासिक घटना को पहली बार पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब हाल ही में देश ने इमरजेंसी लागू होने के 50 वर्षों का कालखंड पूरा किया है, जो विद्यार्थियों को देश के राजनीतिक इतिहास की गहन समझ प्रदान करेगा। पाठ्यपुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि 1970 के दशक की शुरुआत में बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी कुप्रबंधन के आरोपों के कारण तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के प्रति जन-नाराजगी किस प्रकार चरम पर थी। किताब के अनुसार, देश भर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच, जून 1975 में 'आंतरिक अशांति' का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इस दौर का वर्णन करते हुए पुस्तक में उल्लेख है कि कैसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप थोप दी गई।

संपादकीय

भारी पड़ेगा मानसून का रूठना

मानसून की महत्ता को इसी बात से समझ सकते हैं कि कहावतों में इसे भारत का वास्तविक वित्त मंत्री कहा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मानसून की मेहरबानी बहुत मायने रखती है। चूंकि मानसून एक मौसमी परिघटना है,इसलिए उसकी दशा-दिशा भी कई जलवायविक पहलुओं पर निर्भर करती है। ऐसा ही एक पहलू है अल नीनो। इस साल अल नीनो की आशंकाओं ने नीति-नियंताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यह बहुत स्वाभाविक भी है,क्योंकि कई प्रकार की अनिश्चितताओं से उपजी अस्थिरता में कमजोर मानसून वर्तमान स्थितियों को और बिगाड़ने का ही काम करेगा।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्ल्यूएमओ के अनुसार जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो के सक्रिय होने की आशंका 80 प्रतिशत तक है, जो नवंबर तक 90 प्रतिशत तक हो सकती है। अमेरिकी मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि अल नीनो के वर्ष 2026-27 की पूरी सर्दियों तक बने रहने के 96 प्रतिशत तक आसार हैं, जबकि नवंबर से जनवरी के बीच इसके चरम रूप धारण करने की आशंका 63 प्रतिशत तक है। हालात यही संकेत करते हैं कि 1950 के बाद यह अल नीनो का सबसे प्रचंड असर होने जा रहा है। यह किसी मौसमी अनुमान से अधिक रोजगार, खाद्य सुरक्षा, महंगाई और आर्थिक विकास दर पर मंडराते संकट की एक पूर्व चेतावनी है। इसकी अनदेखी करना बहुत भारी पड़ सकता है।

अल नीनो के पीछे के विज्ञान को समझें तो गर्म पानी को पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर धकेलने वाली ट्रेड विंड्स कुछ वर्षों के अंतराल पर कमजोर पड़ जाती हैं। इस स्थिति में वह गर्म पानी वापस पूर्व की ओर फैलता जाता है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा का एक विशाल भंडार उत्सर्जित होता है। यही कारण है कि इतिहास के अब तक के सबसे गर्म साल आमतौर पर अल नीनो के वर्ष ही रहे हैं। पिछली बार वर्ष 2023-24 में इसके प्रचंड रूप ने ही वर्ष 2024 को वैश्विक तापमान के मामले में एक नया रिकार्ड बनाने की दिशा में उन्मुख किया था। यह गर्मी सिर्फ प्रशांत महासागर के ऊपर ही सिमटकर नहीं रहती। विज्ञान की भाषा में यह टेलीकनेक्शंस यानी दूरगामी मौसमी संबंधी परिघटना होती है,जो विश्व भर में वर्षा के रुझान को प्रभावित करती है। इसका एक निश्चित असर भारत में वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानसून पर पड़ता है। इससे न केवल मानसूनी वर्षा में देरी होती है, बल्कि उसकी मात्रा भी संकुचित हो जाती है। इस तरह एक दूरस्थ महासागर में घटित होने वाली परिघटना घरेलू समस्या का रूप धारण कर लेती है।

भारत को फसल उत्पादन और जल स्रोतों को दोबारा भरने के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है, उसके करीब 70 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति मानसून से होती है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही मानसूनी वर्षा के दीर्घकालिक औसत के 92 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है,जो सामान्य से कम श्रेणी में आता है। कमजोर मानसून के व्यापक दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे गर्मी और विकराल रूप धारण कर लेती है,जिससे श्रमिकों की उत्पादकता एवं समग्र उत्पादन प्रभावित होता है। कम बारिश से फसल उत्पादन पर असर से किसान की आमदनी घटती है तो आपूर्ति तंग होने से महंगाई बढ़ती है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है, जहां महंगाई को मापने वाले सूचकांक में खाद्य उत्पादों की बड़ी भारी हिस्सेदारी (47.6 प्रतिशत) है। अप्रैल में पहले ही मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत के स्तर पर पहंच चुकी थी और लगता है कि यह अभी और बढ़ सकती है।

मानसूनी वर्षा में कमी का सबसे बुरा असर देश के उपजाऊ मैदानी इलाकों पर पड़ता है। जून के मध्य तक इस हिस्से में पहले ही वर्षा में करीब 64 से 65 प्रतिशत तक की कमी देखी गई। इससे खरीफ की बोआई प्रभावित होती है। सिंचाई में मुश्किलों के साथ ही उसकी लागत भी बढ़ जाती है। केवल इस रुझान के चलते ही जीडीपी वृद्धि दर में 0.25 प्रतिशत तक की कमी की आशंका हो जाती है। अंतरराष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका नेचर में वर्ष 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन ने इसके पीछे के एक बड़े नकारात्मक पहलू को रेखांकित किया कि इससे ऐसा नुकसान होता है कि बाद में हुई वर्षा भी उसकी भरपाई नहीं कर पाती और इसका चक्रीय प्रभाव करीब अगले तीन वर्षों तक देखा जाता है। इससे खाद्य उत्पादन में गिरावट से महंगाई दर में भी 0.5 से 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आसार बन जाते हैं।

डार्टमाउथ कालेज के एक अर्थशास्त्री का अनुमान है कि प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के चलते वर्ष 2032 तक भारत को करीब एक ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर के आर्थिक उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ सकता है,जबकि वैश्विक स्तर पर यह क्षति 10 ट्रिलियन डालर से भी ऊपर निकल जाएगी। नेचर के उसी अध्ययन में उल्लेख था कि हाल के दौर में आए प्रचंड अल नीनो के कारण दुनिया को वर्ष 1997-98 में 2.1 ट्रिलियन डालर और वर्ष 2015-16 में 3.9 ट्रिलियन डालर का नुकसान हुआ था,जो प्रत्येक बार कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग चार से पांच प्रतिशत था। इतिहास साक्षी है कि कैसे इस प्रकार के संकट मानव जाति के लिए घातक साबित हुए हैं। वर्ष 1877-78 का अल नीनो एक भयावह अकाल का कारण बना था, जिसमें करीब पांच करोड़ लोगों की जान चली गई।

ईरान और अमेरिका के बीच भले ही सुलह हो गई हो,लेकिन दोनों पक्षों के बीच गतिरोध अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में अल नीनो के आसार बड़े खतरे की घंटी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मानना है कि अल नीनो जैसे झटके के साल भर बाद कच्चे तेल की कीमतें करीब 14 प्रतिशत और अन्य वस्तुओं के दाम लगभग पांच प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं। घरेलू मोर्चे पर भीषण गर्मी से निपटने के लिए बिजली की मांग में होने वाला इजाफा कोयला आधारित बिजली उत्पादन को करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। साथ ही साथ,पानी की किल्लत जलविद्युत परियोजनाओं के लिए संकट बढ़ाएगी। यानी अल नीनो का असर जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपायों को भी धक्का पहुंचाता है। स्पष्ट है कि अल नीनो के दुष्प्रभावों से बचने के लिए भारत को प्रत्येक मोर्चे पर हरसंभव जतन करने होंगे।

अनमोल सुविचार

अनुभव एक महान शिक्षक है, इसलिए गलतियों से डरो नहीं, उनसे सीख लो।

महात्मा गांधी

वर्तमान परीक्षा प्रणाली की परीक्षा...

प्रो.शामलाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

कोई जमाना था जब विद्यार्थी लोग गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थी लोग अपने गुरुजनों की देखरेख तथा मार्गदर्शन में सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुकुलों में कहीं भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। जब वह गुरुकुलों से शिक्षा प्राप्त करके बाहर निकलते थे तो वह आदर्श व्यक्ति के तौर पर ही निकलते थे।

तब की तथा अब की शिक्षा प्रणाली में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आजकल गुरुकुलों का स्थान स्कूलों, कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटियों ने ले लिया है।डॉक्टर,वकील,इंजीनियर,प्रशासनिक अधिकारियों आदि उच्च पदों के लिए कोटा,दिल्ली,प्रयागराज आदि महानगरों में कोचिंग सेंटर खुल गए। इन कोचिंग सेंटरों में दाखिला अधिकतम अंकों वाले विद्यार्थियों को ही दिया जाता है। अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए 12 वीं पास विद्यार्थी शुरू से ही पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ ट्यूशन पर भी हजारों रुपया खर्च करते हैं ताकि उपर्युक्त कोचिंग सेंटर में दाखिला ले सके। इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई के दौरान लाखों रुपया खर्च होता है। एक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम एक करोड़ रुपया लगता है। आईआईटी, आई आईएम आदि में दाखिले के लिए बहुत नंबर और पैसा फीस के तौर पर खर्च करना पड़ता है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मां बाप को अपना पेट काट कर बचत करनी पड़ती है,उधार लेना पड़ता है,मकान जायदाद बेचनी या गिरवी रखनी पड़ती है ताकि उनके बच्चे ऊंची पढ़ाई पूरी करके ऊंचे पदों पर आसीन होने के अपने सपने पूरे कर सके। यहां यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि बड़ी-बड़ी डिग्री दिलवाने वाले कोचिंग सेंटर अमीर लोगों के द्वारा शिक्षा के लिए नहीं बल्कि धन कमाने के लिए ही चलाए जाते हैं। बेशक यह कोचिंग सेंटर अपने यहां दाखिल बच्चों को कठिन परिश्रम से शिक्षा देते हैं,बड़ी-बड़ी डिग्रियां प्राप्त करने में सहायता भी करते हैं। लेकिन इन इन कोचिंग केंद्र वालों का संबंध उन लोगों से भी होता है जो की डॉक्टरी या इंजीनियर की डिग्री के लिए परीक्षा पत्र लाखों रुपया लेकर लीक करवाते हैं। जिनके पास लीक किया हुआ प्रश्न पत्र पहले आ जाता है वह उसी के मुताबिक पहले तैयारी कर लेता है और अधिकतम अंक प्राप्त करके ऊंची डिग्री प्राप्त करके उच्च पद पर असीन हो जाता है। लेकिन बहुत बार विद्यार्थी लोग जब प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने-अपने सेंटर में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल हो गया है,उन्हें निराशा होती है,दिल टूट जाता है,मां बाप के द्वारा उधार लेकर उन पर किया हुआ खर्च बेकार जाता हुआ लगता है और उन्हें लगता है कि वह लोग दोबारा पेपर की तैयारी नहीं कर सकेंगे। उनके सपने टूट जाते हैं। अभी कुछ समय पहले नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया। लाखों विद्यार्थियों के सपना चकनाचूर हो गए। कुछ विद्यार्थियों ने आत्महत्या भी कर ली। देश में विद्यार्थियों ने रोश प्रदर्शन किया। सरकार ने नीट की परीक्षा के लिए इंक्वारी कमिटी भी नियुक्त की गई।नीट

की परीक्षा दोबारा बिना कोई फीस लिए कराने का आश्वासन दिया। यह पहली बार है कि किसी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया गया।

नीट जैसी परीक्षा का पेपर आउट होना यह कोई पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी कभी रेलवे की,कभी क्लर्कों की परीक्षा के पेपर लीक होते रहे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया गया के पेपर आउट ना हो। लेकिन परीक्षा व्यवस्था से संबंधित कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा ना ही किसी को सजा मिली । पेपर आउट करने वाला माफिया कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। परीक्षा व्यवस्था से संबंधित कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में किसी ने अभी तक समाधान नहीं किया। जैसे-4000 पदों के लिए दो दो लाख विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं। विभिन्न परीक्षा सेंट्रो पर साथ आए अभिभाविकों के बैठने, पीने के पानी, पंखे आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती। अपने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए उन्हें बसों और रेलगाड़ियों की छत पर बैठकर जाना पड़ता है। किराया खर्च करके जब वह परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है की पेपर लीक हो गया है। उनके अभिभावकों तथा बच्चों के सपने टूट जाते हैं क्योंकि इस पेपर की तैयारी के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया था, लाखों रुपए खर्च किए थे,अब इस तरह से दोबारा प्रयास करना उनके बस की नहीं। पेपर लीक होने का पहले स्त्रोत वह व्यक्ति हो सकता है जो पेपर बनाता है, दूसरा स्त्रोत वह जगह हो सकती है जहां पेपर छपते हैं और तीसरा स्त्रोत वह होता है जो इनके पेपरों की चोरी करता है और पेपर लाखों रुपए में बेचता है। मैं शिक्षा जगत से लंबे समय से जुड़ा रहा हूं। मेरा अनुभव यह कहता है कि किसी न किसी लेवल पर मिली भगत के बिना पेपर लीक नहीं हो सकता। पहले समय में जब प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र में बांटा जाता था तो वहां से किसी चपरासी या क्लर्क के द्वारा पेपर बाहर फोटो स्टेट करा लिया जाता था और नकल करवाने वाले उन प्रश्नों के उत्तर संबंधित विद्यार्थी के पास पहुंचाते थे। लेकिन आजकल परीक्षा व्यवस्था बदल गई है। वर्तमान व्यवस्था में कई बार परीक्षा केंद्र में जितने कंप्यूटर होते हैं उनके मुकाबले में परीक्षा देने वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। एक तरफ उच्च शिक्षा प्राप्त करके युवा लोग डिग्रियां लिए करते हैं और दूसरी तरफ उनको उसके मुताबिक नौकरी नहीं मिलती। नए विद्यार्थियों को पेपर लीक का सामना करना पड़ता है। इन बातों को लेकर देश के विभिन्न नगरों के युवा लोग आक्रोश में है। बहुत साल पहले उपलब्ध नौकरियों को ध्यान में रखकर ही विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाता था। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती। जब कि शिक्षा का क्षेत्र गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए। नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी समय-समय पर पेपर लीक होने,डिग्रियों के बावजूद रोजगार न मिलने के विरोध में युवा लोग विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर करता है। अगर हम अपने देश में डॉक्टर,इंजीनियर, वकील,प्रशासनिक अधिकारी ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त यह है कि इसकी तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों पर विद्यार्थियों का खर्चा कम होना चाहिए, विद्यार्थियों को वैकल्पिक व्यवसाय के बारे में जानकारी देनी चाहिए और कोचिंग सेंटर से संबंधित पेपर लीक करने वाले माफिया के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। यह परीक्षा प्रणाली की परीक्षा है कि क्या परीक्षाएं निर्विघ्नम तरीके से संपन्न हो पाती हैं। सरकारी तंत्र इस संदर्भ में ईमानदार,सख्त तथा निष्पक्ष है।

मादक पदार्थों का बढ़ता साम्राज्य और सिमटते सपने

ड्रग्स के दलदल में धंसती युवा पीढ़ी...

योगेश कुमार गोयल
नजफ्फगढ़, नई दिल्ली

किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी के सपनों,ऊर्जा और सृजनशीलता पर निर्भर करता है लेकिन जब यही युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आने लगे तो यह केवल एक सामाजिक समस्या नहीं रह जाती बल्कि राष्ट्रीय संकट का रूप धारण कर लेती है। आज भारत सहित दुनिया के अनेक देशों के सामने यही चुनौती खड़ी है। युवाओं की प्रतिभा,उनकी सोच, उनकी रचनात्मकता और उनके भविष्य पर नशे का ऐसा ग्रहण लग रहा है,जो न केवल परिवारों को बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को भीतर से खोखला कर रहा है। इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 26 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस'मनाया जाता है। यह दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि पूरी मानवता को चेताने का अवसर है कि यदि नशे के बढ़ते दुष्चक्र को समय रहते नहीं रोका गया तो इसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतने पड़ेंगे। भारत में नशे की समस्या अब महानगरों तक सीमित नहीं रही। यह गांवों, कस्बों, छोटे शहरों और यहां तक कि स्कूलों तथा कॉलेजों तक पहुंच चुकी है। कभी माना जाता था कि नशीले पदार्थों का सेवन केवल संपन्न वर्ग या शहरी संस्कृति की समस्या है लेकिन आज वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अफीम, चरस,गांजा,हेरोइन, सिंथेटिक ड्रग्स और इंजेक्शन के माध्यम से लिए जाने वाले नशीले पदार्थों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। यह स्थिति बताती है कि नशे का नेटवर्क अब समाज की हर परत तक पहुंच चुका है। आज का युवा अनेक प्रकार के दबावों से घिरा हुआ है। प्रतिस्पर्धा,बेरोजगारी, सामाजिक अपेक्षाएं,पारिवारिक तनाव, मानसिक अवसाद,अकेलापन और त्वरित सफलता की चाह उसे भीतर से कमजोर बना रही है। ऐसे में नशे के सौदागर युवाओं की इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। कई बार मित्रों का दबाव, आधुनिक दिखने की चाह, रोमांच की तलाश या क्षणिक सुख का आकर्षण युवाओं को नशे की ओर धकेल देता है। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है लेकिन धीरे-धीरे यही जिज्ञासा लत और फिर विनाश का कारण बन जाती है।

इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने जहां ज्ञान के नए द्वार खोले हैं,वहीं नशे के कारोबार को भी नए साधन उपलब्ध कराए हैं। सोशल मीडिया,एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और डार्क वेब के माध्यम से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पहले से कहीं अधिक आसान हो गई है। अब नशे का सौदा किसी सुनसान गली तक सीमित नहीं बल्कि स्मार्टफोन की स्क्रीन तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे की पहुंच चिंताजनक रूप से बे ती जा रही है। आज देश के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर समय-समय पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। यह विडंबना ही है कि जिन परिसरों में देश के भविष्य का निर्माण होना चाहिए,वहां कुछ युवा अपने भविष्य को स्वयं नष्ट करने की राह पर बढ़ रहे हैं। आधुनिकता और स्वतंत्रता की गलत व्याख्या ने भी इस समस्या को बे ाया है। कई युवाओं को यह भ्रम होता है कि नशा उन्हें अधिक आत्मविश्वासी, रचनात्मक और आधुनिक बनाता है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। नशा व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। उसकी निर्णय लेने की शक्ति कमजोर हो जाती है,स्मरणशक्ति प्रभावित होती है,एकाग्रता घटती है और मानसिक संतुलन बिगे ने लगता है। जो युवा अपने जीवन में बड़े सपने लेकर आगे बढ़ता है,वही नशे की गिरफ्त में आकर अपनी प्रतिभा और संभावनाओं को स्वयं नष्ट कर देता है। यही कारण है कि नशे को केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि मानव संसाधन के विनाश की समस्या माना जाता है।

नशीले पदार्थों का सबसे घातक प्रभाव यह है कि वे व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से गुलाम बना देते हैं। एक बार लत लग जाने पर व्यक्ति उसी प्रभाव को बनाए रखने के लिए लगातार अधिक मात्रा में नशा लेने लगता है। परिणामस्वरूप उसका शरीर कमजोर होने लगता है,भूख कम हो जाती है, वजन घटता है,आंखें लाल रहने लगती हैं, नींद प्रभावित होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई मामलों में व्यक्ति आत्मघाती प्रवृत्तियों का शिकार भी हो जाता है। इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वालों के सामने खतरा और भी गंभीर होता है। एक ही सुई के बार-बार उपयोग से एचआईवी, हेपेटाइटिस और अन्य संक्रमण फैलने की आशंका बे जाती है। यही कारण है कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती बन जाता है।

नशे का अवैध व्यापार दुनिया के सबसे लाभकारी अपराधों में शामिल है। अरबों-खरबों रुपये का यह कारोबार अंतर्राष्ट्रीय तस्करी,आतंकवाद,संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसे गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जैसे नशीले पदार्थों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण मार्ग बनाती है। पाकिस्तान,अफगानिस्तान,म्यांमार और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से आने वाली तस्करी की खेपें भारत के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ड्रग्स का यह अवैध कारोबार अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहा है। ड्रोन,एन्क्रिप्टेड संचार माध्यम,फर्जी पहचान और डिजिटल भुगतान प्रणालियां तस्करों को नई ताकत प्रदान कर रही हैं। ऐसे में केवल पारंपरिक पुलिसिंग से इस समस्या पर नियंत्रण संभव नहीं है। इसके लिए तकनीकी, सामाजिक और कानूनी स्तर पर व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

भारत में हालांकि मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए कड़े कानून मौजूद हैं लेकिन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौती अभी भी बनी हुई है। नशे के खिलाफ ले ई केवल पुलिस,प्रशासन या सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों को अपने बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा। शिक्षण संस्थानों को नशा विरोधी जागरूकता अभियान चलाने होंगे। धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। दरअसल नशे के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार जागरूकता,शिक्षा और सकारात्मक वातावरण है। यदि युवाओं को बेहतर शिक्षा,रोजगार,खेल,कला,संस्कृति और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे नशे जैसे विनाशकारी रास्तों से दूर रह सकते हैं। हमें युवाओं को केवल नशे के दुष्परिणाम बताने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि उन्हें जीवन का सकारात्मक उद्देश्य भी देना होगा।

अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं मादक पदार्थ निषेध दिवस हमें यही संदेश देता है कि नशे के खिलाफ लड़ाई किसी एक दिन का अभियान नहीं बल्कि सतत सामाजिक आंदोलन है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले उसकी युवा शक्ति को नशे के अंधकार से मुक्त करना होगा। देश की युवा सोच पर लगा यह ग्रहण तभी हटेगा,जब सरकार,समाज, परिवार और स्वयं युवा मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवाओं के हाथों में नशे की पुड़िया नहीं, ज्ञान की पुस्तक हो;उनकी आंखों में नशे का धुंधलापन नहीं,सपनों की चमक हो; और उनकी सोच पर नशे का ग्रहण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का उज्ज्वल प्रकाश हो। यही नशा-मुक्त भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव भी।

कौन करे रहम...

राजेन्द्र लाहिरी,
पामगढ़,
छत्तीसगढ़

जो अटल है,अजर-अमर है,
उसकी पीठ में घोंप रहे हो खंजर।
अपनी निर्दयता के मद में चूर,
कर रहे हो वनों को बंजर।

मान लिया इंसान हो,सोच सकते हो,
पर सोच तुम्हारी इतनी गिर गई क्यों?
नोचने को बदनाम हुआ गिद्ध,
पर प्रकृति को तुमने रोज़ नोचा क्यों?

कर रहे हो पर्यावरण का विनाश,
और बेशर्मी से उसे कहते हो
विकास।
जंगलों के सीने में उतार दिए खंजर,
उजाड़ दिया जीवन का हर एहसास।

जो जन्मजात रक्षक थे धरती के,
उन्हें नक्सली कहकर मार दिया।
जो वृक्षों संग जीवन जीते थे,
उनका भी संसार उजाड़ दिया।

एक पेड़ लगाने की औकात नहीं,
पर काटने में तुम सबसे आगे हो।
ये केवल तुम्हारे जीवन की बात नहीं,
असंख्य जीव-जंतु भी इसके भागी हो।

पारिस्थितिकीय तंत्रों पर निर्भर
उनके जीवन का भी यही आधार,
उनके विनाश पर तुम्हारे पास
बस किंतु-परंतु का व्यापार।

आज जंगली प्राणियों पर
अस्तित्व का गहरा संकट है,
पर मानव अब भी समझ न पाया
आने वाला समय कितना विकट है।

वर्षा की कमी पर तिलमिलाते हो,
सूरज की आग में झुलसते जाते हो।
फिर अपने ही रचे संकटों से
चमत्कारों की गुहार लगाते हो।

प्रकृति से रहम की याचना करते हो,
जबकि कुदरत खुद पुकार रही–
धूर्त इंसानों! मुझ पर भी
थोड़ी दया तुम उतारो सही।

वरना समय साफ़ कहता है–
अपने हाथों खुद
विनाशी पथ जाओगे,
यदि प्रकृति पर रहम न किया,
तो इतिहास में बस पछताओगे।

बड़े चेहरों-जातीय संतुलन से सजी यूपी बीजेपी की नई टीम

संजय सक्सेना,लखनऊ,उत्तरप्रदेश

उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिख रही है। पार्टी ने जिस तरह ब्राह्मण,पिछड़ा,दलित और अलग-अलग इलाकों से जुड़े चेहरों को जगह दी है,उससे यह संदेश दिया जा रहा है कि संगठन केवल एक वर्ग या एक क्षेत्र के सहारे नहीं चलेगा, बल्कि हर बड़े सामाजिक समूह को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि नई टीम के गठन में प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद रणनीतिकार सुनील बंसल की छाप नजर आती है। यही वजह है कि इसे सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं,बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कवायद भी माना जा रहा है।

भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में जीत सिर्फ नारे से नहीं,बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और बूथ स्तर की पकड़ से तय होती है। जनसाधारण के नजरिये से देखें तो पार्टी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को भी गंभीरता से लेने की कोशिश की है। नई टीम में इस वर्ग को अपेक्षाकृत अच्छी जगह देकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी एक सामाजिक आधार को कमजोर नहीं होने देगी। इससे यह भी माना जा रहा है कि पार्टी पुराने भरोसेमंद मतदाताओं को फिर से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है,क्योंकि चुनाव के समय संगठन का यह संतुलन बहुत मायने रखता है।सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं में यह बात भी उठ रही है कि सुनील बंसल की भूमिका अब भी उतनी ही अहम है, जितनी पहले थी। वे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को गहराई से समझते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी रणनीति की बड़ी भूमिका मानी गई थी। इसीलिए नई टीम को देखकर बहुत से लोग इसे उसी पुराने संगठनात्मक मॉडल की वापसी के रूप में देख रहे हैं,जिसमें नीचे तक पकड़,सामाजिक गणित और लगातार संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

इसी संदर्भ में संदीप बंसल का नाम भी चर्चा में आ रहा है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वे भी प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसका कारण यह है कि भाजपा अब ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है जो संगठन,वर्ग-संतुलन और चुनावी प्रबंधन तीनों में काम आ सकें। यदि यह प्रवृत्ति आगे बड़ी,तो संदीप बंसल जैसे नेताओं की उपयोगिता और बे सकती है। नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जा रही है कि उसमें केवल चेहरों का नहीं, बल्कि संदेशों का भी संतुलन साधा गया है। एक तरफ पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह सभी बड़े समाजों को साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ यह भरोसा भी देना चाहती है कि चुनावी प्रबंधन पहले की तरह मजबूत हाथों में है। जनता के बीच भी यही धारणा बनती है कि भाजपा संगठन को हल्के में नहीं लेती और हर बड़े चुनाव से पहले अपनी व्यवस्था को फिर से कसती है। खैर,उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को खास तौर पर साधने की कोशिश दिखाई दी है। पार्टी ने 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों के साथ पूरी कार्यकारिणी को नए सिरे से सजा दिया है, जिसमें ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और अवध-कानपुर जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ध्यान से रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची में सुरेश राणा,सत्यपाल सैनी,ब्रज बहादुर सिंह,डॉ. धर्मेंद्र सिंह,मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी,प्रियंका रावत,दुर्विजय शाक्य,रमेश सिंह,नीरज सिंह,अर्चना मिश्रा,पूजा पाल,शंकर गिरी,कामेश्वर सिंह,डॉ. कृतिका अग्रवाल,सुरेश मौर्य,राजेश यादव,कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी,ब्रज बहादुर सिंह,डॉ.धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल,देवेश कोरी,प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य,रमेश सिंह,नीरज सिंह,अर्चना मिश्रा,पूजा पाल,शंकर गिरी,कामेश्वर सिंह,डॉ. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य,राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता जैसे नाम अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का संदेश देते हैं।

प्रदेश महामंत्रियों में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य,अभिजात मिश्रा,उपेंद्र रावत,संजय राय, शंकर लोधी,दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जगह मिली है।इन नामों के जरिए पार्टी ने ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है. यह भी संकेत मिलता है कि संगठन में केवल पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं किया गया, बल्कि चुनावी प्रबंधन में काम आ सकने वाले मिश्रित नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है।
प्रदेश मंत्रियों की सूची भी इसी सामाजिक गणित को आगे बढ़ाती है, जो नाम प्रमुखता से सामने आए हैं,उनमें शंकर गिरी,डॉ. चंद्रमोहन सिंह, मीना चौबे,अंजुला सिंह माहौर,विजय शिवहरे,शंकर लोधी,शकुंतला चौहान,अनामिका चौधरी,पूनम बजाज,अर्चना मिश्रा,अमित बाल्मीकि,बसंत त्यागी,शिवभूषण सिंह,सुरेश पासी,अभिजात मिश्रा और डीपी भारती शामिल हैं। इन नियुक्तियों से पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में हर बड़े सामाजिक वर्ग को हिस्सेदारी दी जा रही है। क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा भी इस फेरबदल का अहम हिस्सा रही।

कुल मिलाकर यह नई टीम केवल पदों का बंटवारा नहीं,बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने वाला संगठनात्मक ढांचा मानी जा रही है। पार्टी ने सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और चुनावी प्रबंधन तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की है। जाति के हिसाब से देखें तो इस सूची में ब्राह्मण,क्षत्रिय,यादव,शाक्य,लोधी,सैनी, पासी,बाल्मीकि,शाक्य,मौर्य,रावत,कोरी, चौहान,जाटव और अन्य पिछड़े-दलित समुदायों की मौजूदगी साफ दिखती है. यही वजह है कि इसे महज संगठनात्मक बदलाव नहीं,बल्कि राजनीतिक संदेश वाली टीम माना जा रहा है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

जीएसटी चोरी पर आखिर कब लगेगी लगाम?

जब तक संरक्षण की चर्चाओं पर विराम नहीं और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं,तब तक राजस्व का रिसाव रुकना मुश्किल

अंबिकापुर में 'आधा बिल-आधा बिना बिल' के कारोबार की चर्चाएं ट्रांसपोर्ट से खुदरा बाजार तक कर चोरी के तरीकों पर उठ रहे सवाल

राज्य में एफआईआर के निर्देश,लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल

अंबिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का उद्देश्य पूरे देश में एक पारदर्शी और जवाबदेह कर व्यवस्था स्थापित करना था,ताकि व्यापारिक लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रहे और कर चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके,लेकिन जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो कई व्यापारिक क्षेत्रों में आज भी जीएसटी चोरी की चर्चाएं खुलेआम होती हैं। व्यापारियों,उपभोक्ताओं और कर सलाहकारों के बीच लंबे समय से यह चर्चा है कि कई जगहों पर माल की वास्तविक खरीद-बिक्री और बिलिंग में बड़ा अंतर रहता है,सवाल यह है कि क्या इस पूरे तंत्र से विभाग अनजान है,या फिर जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही? हाल ही में प्रदेश में जीएसटी चोरी के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए,जिससे यह उम्मीद जगी कि अब बड़े स्तर पर कर चोरी के खिलाफ अभियान चलेगा,लेकिन दूसरी ओर अंबिकापुर जैसे शहर में लंबे समय से उठ रहे सवालों के बावजूद कार्रवाई का अभाव लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है,आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ मामलों में विभाग सक्रिय दिखाई देता है और कुछ मामलों में वर्षों तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आता?

ट्रांसपोर्ट से दुकान तक... हर चरण पर जांच की जरूरत

जीएसटी चोरी केवल दुकान पर बिल न देने तक सीमित नहीं मानी जाती,कर विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कहीं अनियमितता होती है तो उसकी शुरुआत माल की आपूर्ति से ही हो जाती है, सवाल यह भी है कि ट्रांसपोर्ट के दौरान भेजे गए माल और बिल में कितना मेल है? ई-वे बिल और वास्तविक माल का मिलान नियमित रूप से होता है या नहीं? बड़े गोदामों और थोक व्यापारियों का जोखिम आधारित ऑडिट कितनी बार किया जाता है? क्या विभाग डिजिटल डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध लेन-देन की पहचान कर रहा है? यदि इन सभी स्तरों पर प्रभावी निगरानी हो तो कर चोरी की संभावनाएं काफी हद तक कम हो सकती हैं।

केवल एक प्रतिष्ठान नहीं,पूरे बाजार की होनी चाहिए निष्पक्ष जांच-अंबिकापुर में पूर्व में एक इलेक्ट्रिकल प्रतिष्ठान को लेकर जीएसटी संबंधी सवाल सार्वजनिक रूप से उठ चुके हैं, उस मामले में शिकायतें भी सामने आई और बाजार में काफी चर्चा हुई,लेकिन व्यापारिक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा यह मानता है कि यदि जांच निष्पक्ष और व्यापक हो तो मामला किसी एक प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं रहेगा,स्थानीय लोगों का कहना है कि कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में बिलिंग और वास्तविक कारोबार के बीच अंतर की जांच आवश्यक है, यदि विभाग निष्पक्ष अभियान चलाए तो वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

क्या जीएसटी कार्यालय के सामने ही हो रहा खेल?-अंबिकापुर में जीएसटी विभाग का कार्यालय मौजूद है,इसके बावजूद यदि बाजार में लगातार कर चोरी की चर्चाएं होती रहें तो स्वाभाविक रूप से विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठते हैं, क्या विभाग को इन गतिविधियों की जानकारी नहीं? यदि जानकारी है तो कार्रवाई क्यों सीमित दिखाई देती है? क्या नियमित निरीक्षण पर्याप्त नहीं हैं? क्या जोखिम वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर विशेष जांच की जा रही है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर विभाग को देना चाहिए।

राजस्व का नुकसान केवल सरकार का नहीं,जनता का भी-जीएसटी से प्राप्त राजस्व ही सड़कों,अस्पतालों,स्कूलों,पेयजल योजनाओं और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च होता है,यदि कर चोरी होती है तो उसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ता है,यानी नुकसान केवल सरकारी खजाने का नहीं बल्कि पूरे समाज का होता है,इसलिए जीएसटी चोरी केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सार्वजनिक हित से जुड़ा

'आधा बिल-आधा नगद' का मॉडल,बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी की...

व्यापारिक जगत में सबसे अधिक जिस तरीके की चर्चा होती है,वह है 'आधा बिल-आधा बिना बिल' का कथित कारोबार,बाजार से जुड़े लोगों का कहना है कि कई बार व्यापारी जितना माल वास्तव में खरीदते हैं, उसका पूरा बिल नहीं लिया जाता,उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यापारी ने 50 लाख रुपये का माल खरीदा,तो आरोप है कि केवल 25 लाख रुपये का बिल जारी कराया जाता है,जबकि शेष माल का भुगतान नगद या अन्य माध्यमों से कर दिया जाता है,ऐसी स्थिति में जीएसटी केवल बिल वाले हिस्से पर जमा होता है, जबकि बाकी कारोबार कर व्यवस्था से बाहर रह जाता है,यदि ऐसा हो रहा है तो यह केवल कर चोरी नहीं,बल्कि सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान पहुंचाने का मामला है।

जहां बैंकिंग लेन-देन,वहीं जीएसटी... बाकी 'उचंती' में?

व्यापारिक सूत्रों के अनुसार कई स्थानों पर बैंकिंग माध्यम से किए गए लेन-देन पर तो विधिवत जीएसटी बिल जारी किए जाते हैं,लेकिन नगद भुगतान वाले लेन-देन में पूरी पारदर्शिता नहीं रहती,यही वह जगह है जहां राजस्व को सबसे अधिक नुकसान होने की आशंका जताई जाती है,यदि वास्तविक कारोबार और बिलिंग के बीच बड़ा अंतर है,तो इसका सीधा प्रभाव सरकार के कर संग्रह पर पड़ता है।

अब केवल कार्रवाई नहीं,पारदर्शिता भी जरूरी

जीएसटी विभाग की विश्वसनीयता तभी मजबूत होगी जब कार्रवाई निष्पक्ष,पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होगी,यदि बाजार में कर चोरी की चर्चाएं निराधार हैं तो विभाग को तथ्य सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,यदि कहीं अनियमितताएं हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का भय तभी स्थापित होगा जब नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे,जीएसटी व्यवस्था का मूल उद्देश्य कर संग्रह बढ़ाना ही नहीं, बल्कि व्यापार में पारदर्शिता लाना भी है, इसलिए अब समय आ गया है कि विभाग केवल शिकायतों पर निर्भर रहने के बजाय व्यापक जोखिम विश्लेषण,नियमित ऑडिट और तकनीकी निगरानी के माध्यम से यह विश्वास दिलाए कि छत्तीसगढ़ में कर चोरी करने वाला चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

घटती घटना
सरगुजा समाचार
अम्बिकापुर शुक्रवार 22 मई 2026
3

शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं...नवापारा के चर्चित 'बंसल इलेक्ट्रिकल्स' मामले में विभागीय चुप्पी पर उठ सवाल

'कच्चे बिल और अलग-अलग खातों' के आरोपों पर अब तक जांच शुरू नहीं होने से बाजार में चर्चा तेज

ईमानदार व्यापारी भी होते हैं प्रभावित

बाजार में बड़ी संख्या ऐसे व्यापारियों की भी है जो हर लेन-देन का विधिवत बिल जारी करते हैं और समय पर जीएसटी जमा करते हैं, लेकिन यदि कुछ लोग कर चोरी कर अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं तो इसका सबसे अधिक नुकसान उन्हीं ईमानदार व्यापारियों को होता है, क्योंकि उन्हें असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, इसलिए निष्पक्ष कार्रवाई ईमानदार व्यापारियों के हित में भी आवश्यक है।

जनता पूछ रही है...

- क्या अंबिकापुर में व्यापक जीएसटी ऑडिट होगा?
- क्या बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों की विशेष जांच होगी?
- क्या ई-वे बिल और वास्तविक स्टॉक का मिलान कराया जाएगा?
- क्या बिना बिल बिक्री पर विशेष अभियान चलेगा?
- क्या विभाग केवल शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेगा या स्वयं भी जांच करेगा?

ज्वाइंट कमिश्नर राखी अग्रवाल का कहना...

ज्वाइंट कमिश्नर राखी अग्रवाल ने बताया कि बंसल इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित समाचार प्रकाशन के बाद संबंधित मामले को गंभीरता से लिया गया है,उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं,जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यापारी द्वारा बिना वैध जीएसटी बिल के सामान का क्रय-विक्रय किया जा रहा है अथवा जीएसटी नियमों का उल्लंघन किया गया है,तो ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

डिप्टी कमिश्नर एस.आर. भगत का कहना

डिप्टी कमिश्नर एस.आर. भगत ने कहा कि जीएसटी चोरी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी,यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि किसी व्यापारी द्वारा कर चोरी,बिना बिल कारोबार अथवा अन्य प्रकार की जीएसटी संबंधी अनियमितता की गई है,तो संबंधित व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी,विभाग कर चोरी के मामलों पर लगातार निगरानी रख रहा है और प्राप्त शिकायतों तथा तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

फायर सेफ्टी ऑडिट में 24 कोचिंग व हॉस्टल फेल,एक सप्ताह का अल्टीमेटम

फायर सिस्टम,इमरजेंसी एग्जिट और चौड़े प्रवेश मार्ग बनाने के निर्देश,दोबारा जांच में कमी मिली तो होगी तालाबंदी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)।

शहर में संचालित निजी कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों की फायर सेफ्टी व्यवस्था जांच में गंभीर रूप से लापरवाह मिली है। दमकल विभाग की ओर से पिछले दो दिनों से चलाए जा रहे विशेष फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान 24 निजी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों में आवश्यक अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और कमियां बरकरार मिलने पर संबंधित संस्थानों में तालाबंदी सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों और अन्य भीड़भाड़ वाले भवनों में आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबिकापुर में दमकल विभाग की टीम ने विभिन्न निजी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों का फायर सेफ्टी ऑडिट किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश संस्थानों में अग्निशमन यंत्र या तो पर्याप्त संख्या में नहीं मिले या उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। कई जगह फायर अलार्म सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर, आपातकालीन निकास (इमरजेंसी एग्जिट) और फायर फाइटिंग सिस्टम का अभाव पाया गया। कुछ भवनों में प्रवेश मार्ग और सीढ़ियां इतनी संकरी मिलीं कि आपात स्थिति में छात्रों की सुरक्षित निकासी मुश्किल हो सकती है। कई स्थानों पर निकास मार्गों पर सामान रखा होने से भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाया गया।

मॉक ड्रिल कराने की सलाह : दमकल विभाग ने सभी संचालकों को एक सप्ताह के भीतर अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर और अन्य सुरक्षा उपकरण स्थापित करने,उन्हें चालू स्थिति में रखने तथा भवनों के प्रवेश मार्ग और सीढ़ियों की चौड़ाई निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी संस्थानों को आपदा की स्थिति में सुरक्षित निकासी की योजना तैयार करने और नियमित मॉक ड्रिल कराने की भी सलाह दी गई है।

एक सप्ताह बाद दोबारा निरीक्षण : अधिकारियों ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। एक सप्ताह बाद सभी संस्थानों का दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि इस दौरान कमियां दूर नहीं मिलीं तो संबंधित कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों के खिलाफ नियमानुसार सीलिंग,तालाबंदी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दमकल विभाग का कहना है कि यह अभियान केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि भीड़भाड़ वाले शैक्षणिक संस्थानों में संभावित आगजनी की घटनाओं को रोकने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

लंदन से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर महिला से डेढ़ लाख की ठगी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)।

इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर लंदन से महंगे गिफ्ट भेजने और व्यवसाय में लाभ दिलाने का झांसा देकर साइबर ठग ने शहर की एक महिला से एक लाख 53 हजार रुपए ठग लिए। ठगी का एहसास होने पर महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, नमनाकला निवासी महिला की 15 जून को इंस्टाग्राम के माध्यम से एक युवक से पहचान हुई। युवक ने अपना नाम रवि कुमार अग्रवाल बताते हुए खुद को लंदन में व्यवसायी बताया। बातचीत के दौरान उसने महिला से व्हाट्सएप पर संपर्क किया और कुछ ही दिनों में विश्वास जीत लिया। आरोपी ने महिला को व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने का लालच दिया और लंदन से कीमती गिफ्ट भेजने की बात कही। शुरुआत में महिला ने मना कर दिया, लेकिन बार-बार आग्रह करने पर उसने अपना पता साझा कर दिया। 18 जून की सुबह महिला के पास एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को कूरियर कंपनी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उसके नाम लंदन से भेजे गए पार्सल में सोना, डायमंड सहित अन्य कीमती सामान है। पार्सल लेने के लिए कस्टम शुल्क जमा कराने की बात कही गई। महिला ने इसकी जानकारी रवि अग्रवाल को दी तो उसने भरोसा दिलाया कि वह लंदन से पौंड भेज देगा और फिलहाल कस्टम चार्ज जमा कर दें। उसके झांसे में आकर महिला ने पहले 27 हजार रुपए धमखील लोखंडे नामक व्यक्ति के खाते में जमा कर दिए। इसके बाद आरोपी ने फिर संपर्क कर कहा कि लंदन से भेजी गई राशि को भारत में एक्सचेंज कराने के लिए 45 हजार रुपए टैक्स देना होगा। महिला ने मना किया तो आरोपी ने अपने दस्तावेज फंसने और करियर खराब होने की बात कहकर भावनात्मक दबाव बनाया। इसके बाद महिला ने 45 हजार रुपए बैंक में और 81 हजार रुपए च्वाइस सेंटर के माध्यम से जमा कर दिए। आरोपी ने इसके बाद व्हाट्सएप पर दिल्ली आने का फर्जी हवाई टिकट भेजते हुए भरोसा दिलाया कि वह खुद पार्सल लेकर अंबिकापुर पहुंचेगा। 19 जून को उसने फिर फोन कर पार्सल देने के नाम पर 63 हजार रुपए और मांगे। इस बार महिला को ठगी का एहसास हुआ और उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने संपर्क बंद कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आकाशीय बिजली गिरने से दो गायों की मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत करिंदा में गुरुवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से दो गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार ग्राम करिंदा निवासी किसान गुलाब, पिता ज्योत राम की दो गायें गुरुवार दोपहर करीब एक बजे खेत के पास चर रही थीं। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। इसकी चपेट में आने से दोनों गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। किसान ने प्रशासन से प्राकृतिक आपदा के तहत मुआवजा दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रभावित किसान को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कबीरसाय राजवाडे पिता नेतराम राजवाडे निवासी ग्राम सरईटिकरा तहसील व थाना अम्बिकापुर आवेदक स्वयं के जन्म दिनांक 24/05/1965 को स्थान सरईटिकरा में आ है। आवेदक के जन्म उपरांत जन्म पंजीयन नहीं कराया गया है अतः जन्म प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

उक्त संबंध में यदि किसी को कोई आप्पति हो तो ईस्तहार प्रकाशन से 15 दिवस तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा / आपत्ति पेश कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक 25/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं यायालयीन मुद्रा से जारी।

सील

तहसीलदार
अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार -2 अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,(छ0ग0)

रा0प्र0क्र0.202606021700032 / ब-121 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नकुल राम आ0 स्व0 भगवती राम, निवासी शक्तिनगर जरही, तहसील प्रतापपुर जिला- सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम ठाकुरपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 697/7 रकबा 0.010 हे0 (2.5 डिसमिल) एवं उस पर निर्मित मकान को निजी कार्य हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अनावेदक नन्दकिशोर गोस्वामी आठ स्व0 अभिमन्यु गोस्वामी, निवासी मायापुर अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) को रू0 25,00,000/- (पच्चीस लाख रूपये) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 17/07/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेश कुमार आ.स्व. जीवन राम अग्रवाल, उम्र- 65 वर्ष, जाति- अग्रवाल निवासी ब्रम्ह मंदिर के पास ब्रम्हपारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदक कृष्ण कुमार आ.स्व. जीवन राम अग्रवाल, उम्र-73 वर्ष, निवासी राम मंदिर रोड़ ब्रम्ह वार्ड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 11क मोहल्ला- राम मंदिर मैदान स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3196/4813/119 रकबा 0.03/21/2 भूमि स्थित है। उक्त भूखण्ड में से अनावेदक द्वारा रकबा 0.01 ग एकड़ भूमि का पंजीकृत हकत्याग विलेख दिनांक 26.05.2026 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध हकत्याग विलेख के आधार पर आवेदित भूमि से अनावेदक का नाम विलोपित कर सम्पूर्ण रकबे पर आवेदक द्वारा स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु पंजीबद्ध हकत्याग विलेख की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10/ 07/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

आज दिनांक- 24/06/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मै कै लाश तिग्गा माता/पिता/पालक का नाम) सुपुत्र/सुपुत्री झरिया तिग्गा गाँव/शहर सिकटापारा ग्राम ढेलसरा,थाना व तहसील सीतापुर जिला -सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य ने अपने नाबालिग सुपुत्र/सुपुत्री का नाम अभिनय तिग्गा (ABHINAY TIGGA) (पुराना नाम) से बदल कर अविनाश तिग्गा (AVINASH TIGGA) (नया नाम) रख लिया है।

पालक
कैलाश
सिकटापारा ग्राम ढेलसरा,
सीतापुर जिला-सरगुजा छत्तीसगढ़

नाम परिवर्तन सूचना

प्रारूप-(एक)

मैं जमेश्वरी (Jameshvari) पत्नी जागेश्वर गोंड (Jageshvar Gond) निवासी-मकान नंबर 66, खुटनपारा, ग्राम अमगांव, तहसील - लुंड्रा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ (497101) ने अपना नाम जमेश्वरी (Jameshvari) से बदल कर/सुधारकर जागेश्वरी (Jageshwari) रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नए/सही नाम से जाना और पहचाना जाए ।

आवेदक
जागेश्वरी
ग्राम अमगांव,तहसील-लुंड्रा,
जिला सरगुजा,छत्तीसगढ़

कार्यालय,कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (वि/यां) संभाग-अम्बिकापुर,छ0ग0

निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक-2449/NIT-04/2026 2027 / व ले लि दिनांक 22/06/2026

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 03/07/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- 10/07/2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :- 13/07/2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे से

कार्यों हेतु

निविदा प्रपत्र का मूल्य - 750.00 रूपये, निविदाकारों की श्रेणी - ई-पंजीयन के अंतर्गत 'द' से 'अ' तक तथा कार्य की अवधि दिनांक 31.03.2027 तक वर्षा ऋतु सहित निर्धारित है।

एन.आई.टी.क्र. निविदा क्र0	कार्य का नाम NoOfCalls	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) - अमानत राशि (रू. मे). बैंक साल्वेंसी (रू. में)
T0010	कोरिया जिले के अंतर्गत नवीन तहसील भवन पटना में विधुतीकरण का कार्य । // सिविल जमा कार्य //	5.77-5000.00-86550.00
T0011	कोरिया जिले के अंतर्गत सखी वन स्टॉप सेंटर में विधुतीकरण कार्य । // सिविल जमा कार्य //	4.68-4680.00-70200.00
T0012	जिला कोरिया के अमरपुर-चिरमिरी मुख्य जिला मार्ग से लावापारा-झलरापारा होते हुए बाबा पहरी मुख्य मार्ग तक पोल शिफ्टिंग का कार्य (बजट कार्य)	4.40-4400.00-66000.00

निविदा संबंधी अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभागीय संभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (वि/यां)
संभाग अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

जी0नं0 -262701672/2

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव

क्रमांक /2434/स्टोर/2026 अम्बिकापुर, दिनांक 19/06/26

ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम निविदा आमंत्रण सूचना

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) की ओर से वाहन स्टैण्ड संचालन के निविदा हेतु फर्मों / अभिकरणों से राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in में देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा का नाम	सी.जी.ई.प्रोक्यो निविदा क्रमांक	ऑनलाईन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	शासकीय चिकित्सा ह्याविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,अम्बिकापुर में वाहन स्टैण्ड का संचालन	193826	24.06.2026, 10:00 AM	09.07.2026, 02:00 PM	09.07.2026, 03:00 PM	09.07.2026, 04:00 PM

स्थान - कार्यालय, संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,
अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)

जी0नं0 -262701662/2

CMYK

15 के बाद 11 फिर फरार...आखिर किसकी निगरानी में चल रहा संप्रेक्षण गृह?

दो फरारी कांड, एक ही अधिकारी का कार्यकाल...आखिर कब तय होगी जवाबदेही?

संप्रेक्षण गृह या फरारगृह? चार महीने में दूसरी बार सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त

चार महीने में दूसरी बड़ी फरारी,बाल संरक्षण विभाग की सुरक्षा व्यवस्था फिर बेनकाब

बाल संरक्षण विभाग की बड़ी चूक ! संप्रेक्षण गृह से फिर 11 अपचारी बालक फरार

संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा भगवान भरोसे ! 11 अपचारी बालक फरार...विभाग फिर कठघरे में...

खिड़की टूटी या पूरी व्यवस्था? संप्रेक्षण गृह से फरारी ने खोली बाल संरक्षण तंत्र की पोल

सुरक्षा के दावे कागजों में,अपचारी बालक सड़कों पर... आखिर जिम्मेदार कौन?

फरवरी में 15, जून में 11 अपचारी बालक भागे, अब तक 4 लौटे,7 की तलाश जारी...आखिर कब जागेगा बाल संरक्षण विभाग?

जिला कार्यक्रम अधिकारी जगदेव राम प्रधान के कार्यकाल में दो बार फरारी,सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद, फिर भी मीडिया के सामने भेजा गया हाउस फादर,पूरे तंत्र की जवाबदेही पर उठा प्रश्न

-संवाददाता-

अंबिकापुर,25 जून (घटती-घटना)। अंबिकापुर स्थित संप्रेक्षण गृह से 11 अपचारी बालकों के फरार होने की घटना ने एक बार फिर महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल संरक्षण व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है,यह घटना इसलिए और भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि महज चार महीने पहले फरवरी 2026 में भी प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बालक फरार हो गए थे,उस समय विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, समीक्षा करने और आवश्यक सुधार के बड़े-बड़े दावे किए थे,लेकिन अब फिर 11 बालकों का एक साथ फरार हो जाना उन सभी दावों की पोल खोलता नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के समय संप्रेक्षण गृह में कुल 31 अपचारी बालक मौजूद थे,इनमें से 11 बालक खिड़की के रास्ते निकलकर फरार हो गए, ताजा जानकारी के अनुसार अब तक चार बालक वापस आ चुके हैं, जिनमें से एक को उसका परिवार स्वयं लेकर आया है,जबकि सात अन्य बालकों की तलाश पुलिस और प्रशासन द्वारा की जा रही है,लगातार दूसरी बार हुई इस घटना ने केवल सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सबसे अधिक सवाल महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जगदेव राम प्रधान के कार्यकाल पर उठ रहे हैं, क्योंकि चार महीने के भीतर दो बार इतनी बड़ी सुरक्षा चूक होना सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही माना जा रहा है।

लगातार विवादों में रहे जिला कार्यक्रम अधिकारी, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं?

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जगदेव राम प्रधान का नाम केवल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था में सामने आई चूकों तक सीमित नहीं है, उनके कार्यकाल में पूर्व में भी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर विवाद सामने आते रहे हैं,उपलब्ध शिकायतों और अभिलेखों के अनुसार अंबिकापुर और मनेन्द्रगढ़–दोनों स्थानों पर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए कई शिकायतें विभाग और शासन स्तर तक भेजी गई थीं,शिकायतकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और जांच की मांग की थी, अब जब उनके कार्यकाल में महज चार महीने के भीतर दो बार अपचारी बालकों के फरार होने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, तो यह सवाल और गहरा हो गया है कि क्या विभाग ने कभी उनके कार्य निष्पादन और प्रशासनिक निर्णयों का समग्र मूल्यांकन किया?

चार महीने... दो बड़ी फरारी... आखिर जिम्मेदार कौन?

फरवरी 2026 में प्लेस ऑफ सेफ्टी से 15 अपचारी बालकों के भागने की घटना सामने आई थी,उस समय विभागीय अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, सुरक्षा ऑडिट,अतिरिक्त निगरानी और आवश्यक सुधार के दावे किए थे,अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी,लेकिन चार महीने बाद जून में फिर 11 अपचारी बालकों का फरार हो जाना यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर फरवरी की घटना से विभाग ने सीखा क्या? क्या सुरक्षा ऑडिट केवल कागजों तक सीमित रहा? क्या कमजोर स्थानों की पहचान नहीं की गई? क्या सुरक्षा व्यवस्था में सुधार केवल फाइलों में दर्ज होकर रह गया? यदि सुधार हुआ था तो उसका परिणाम कहां दिखाई देता है? लगातार दूसरी घटना यह संकेत देती है कि पहली घटना के बाद उठाए गए कदम या तो पर्याप्त नहीं थे या फिर उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही नहीं हुआ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यकाल में दो बार फरारी,क्या जवाबदेही तय होगी?

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी जगदेव राम प्रधान के कार्यकाल में चार महीने के भीतर यह दूसरी बड़ी फरारी की घटना है,पहली बार 15 बालक भागे,दूसरी बार 11 बालक भाग गए, यानी कुल 26 अपचारी बालक सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर बाहर निकलने में सफल रहे, ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या विभाग केवल अधीनस्थ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करेगा या शीर्ष स्तर पर भी जवाबदेही सुनिश्चित होगी? जब किसी विभाग में लगातार एक जैसी गंभीर घटनाएं होती हैं तो प्रशासनिक जिम्मेदारी केवल निचले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहती, यदि सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा था तो फिर यह व्यवस्था धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दी?

सवाल स्थानीय मंत्री से भी...

महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री स्वयं क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब एक ही अधिकारी को लेकर बार-बार शिकायतें,भर्ती विवाद और अब सुरक्षा व्यवस्था में लगातार विफलता जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं,तो विभागीय स्तर पर क्या समीक्षा की गई? यदि शिकायतें निराधार थीं, तो उनका सार्वजनिक रूप से निराकरण क्यों नहीं किया गया? यदि शिकायतें प्रथम दृष्टया गंभीर थीं, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई? और यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या इसे प्रशासनिक उदासीनता माना जाए?

अब जवाबदेही तय करने का समय

चार महीने में दो बार बालकों का फरार होना केवल संयोग नहीं माना जा सकता,यदि पहले भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सवाल उठे,फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर घटनाएं सामने आई,तो सरकार और विभाग दोनों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि पूरे कार्यकाल की निष्पक्ष समीक्षा कराई जाए,जनता अब यह जानना चाहती है कि क्या लगातार शिकायतों के बावजूद अधिकारी को संरक्षण मिलता रहा? क्या विभाग ने शिकायतों की जांच पूरी की? क्या भर्ती संबंधी शिकायतों और वर्तमान प्रशासनिक विफलताओं के बीच कोई व्यापक प्रशासनिक समीक्षा होगी? क्या जवाबदेही केवल अधीनस्थ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या शीर्ष अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होगी? यदि शासन पारदर्शिता का दावा करता है, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी सार्वजनिक होने चाहिए,इससे न केवल विभाग की विश्वसनीयता बढ़ेगी,बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में भी मदद मिलेगी।

वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे,फिर मीडिया के सामने क्यों भेजा गया हाउस फादर?

घटना के बाद कलेक्टर,एसडीएम,जिला कार्यक्रम अधिकारी,प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी संप्रेक्षण गृह पहुंचे,निरीक्षण हुआ,बैठक हुई, समीक्षा हुई, लेकिन जब मीडिया ने सवाल पूछे तो सामने कौन आया? हाउस फादर,यह बात कई पत्रकारों और लोगों को हैरान कर गई,जब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने आकर घटना की जानकारी क्यों नहीं दी? क्या विभाग घटना को लेकर असहज था? क्या जिम्मेदारी तय होने की आशंका के कारण वरिष्ठ अधिकारी सामने आने से बचते रहे? या फिर विभाग निचले कर्मचारियों को आगे कर अपनी जवाबदेही से बचना चाहता था?

पुरानी खिड़की का तर्क... लेकिन जिम्मेदारी किसकी?

घटना के बाद विभाग की ओर से कहा गया कि जिस खिड़की से बालक भागे वह पुरानी थी, लेकिन यह तर्क अपने साथ कई नए प्रश्न भी लेकर आता है, यदि खिड़की पुरानी थी तो क्या विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या नियमित निरीक्षण नहीं होता था? क्या किसी अधिकारी ने इसे बदलने या मजबूत करने की अनुशंसा नहीं की? जब वहां अपचारी बालक रखे जाते हैं तो क्या मजबूत ग्रिल और सुरक्षित संरचना प्राथमिक आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? यदि खिड़की कमजोर थी तो यह केवल निर्माण संबंधी समस्या नहीं बल्कि नियमित रखरखाव और प्रशासनिक निगरानी की भी विफलता है।

अनुभवी काउंसलर को जिला कार्यालय, अनुभवहीन को संप्रेक्षण गृह... आखिर क्यों?-सूत्रों के अनुसार जिले के अनुभवी काउंसलर को जिला कार्यालय में अटैच कर दिया गया,जबकि संप्रेक्षण गृह जैसे संवेदनशील संस्थान में अपेक्षाकृत अनुभवहीन व्यक्ति को बालकों की काउंसलिंग का दायित्व सौंपा गया, यदि यह तथ्य सही है तो यह भी जांच का विषय है, अपचारी बालकों के पुनर्वास में काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसे में अनुभवी व्यक्ति को हटाकर कम अनुभव वाले कर्मचारी को जिम्मेदारी देने का आधार क्या था? क्या इस निर्णय का प्रभाव संस्थान के अनुशासन और सुरक्षा पर पड़ा?

अंदर जाने की अनुमति केवल दो-तीन कर्मचारियों को...आखिर क्यों?-सूत्रों के अनुसार संप्रेक्षण गृह के अंदर नियमित रूप से केवल दो-तीन कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति थी, यदि ऐसा है तो इसका कारण क्या है? क्या यह विभागीय नियम है? या फिर किसी विशेष व्यवस्था के तहत ऐसा किया जा रहा था? यदि अधिकांश कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी तो निगरानी व्यवस्था कैसे संचालित हो रही थी? इस विषय पर विभाग को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने क्या कहा?-प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी विक्रमांक सिंह के अनुसार अब तक चार अपचारी बालक वापस आ चुके हैं,इनमें से एक बालक को उसका परिवार स्वयं लेकर आया,बाकी सात बालकों की तलाश लगातार जारी है,उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार खोजबीन कर रही है।

लाखों का बजट... लेकिन सुरक्षा भगवान भरोसे?

बाल संरक्षण संस्थानों के संचालन,भोजन, सुरक्षा,काउंसलिंग, निगरानी और रखरखाव पर हर वर्ष लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं,लेकिन यदि चार महीने में दो बार बालक फरार हो जाएं, सीसीटीवी अधूरे हों,कमजोर खिड़कियां बनी रहें,सुरक्षा व्यवस्था विफल हो जाए, वरिष्ठ अधिकारी जवाब देने से बचें, तो जनता यह पूछने को मजबूर है कि आखिर सरकारी धन खर्च कहां हो रहा है?

घटती घटना | सरगुजा समाचार | अम्बिकापुर गुरुवार 25 जून 2026 | 3

जनता पूछ रही है...

- फरवरी में 15 और जून में 11 बालक कैसे भाग गए?
- जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यकाल में लगातार सुरक्षा चूक क्यों हो रही है?
- पहली घटना में किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई?
- पुरानी खिड़की को समय रहते बदला क्यों नहीं गया?
- पूरे परिसर में सीसीटीवी क्यों नहीं लगाए गए?
- अनुभवी काउंसलर को जिला कार्यालय क्यों भेजा गया?
- केवल दो-तीन कर्मचारियों को ही अंदर जाने की अनुमति क्यों?
- क्या इस बार भी केवल जांच समिति बनाकर मामला समाप्त कर दिया जाएगा?

यह केवल फरारी नहीं...पूरे बाल संरक्षण तंत्र की परीक्षा है...

अंबिकापुर की यह घटना केवल 11 अपचारी बालकों के फरार होने का मामला नहीं है, यह उस व्यवस्था की परीक्षा है,जो कानून के संरक्षण में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, निगरानी और पुनर्वास की जिम्मेदारी निभाती है,यदि चार महीने में दो बार इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और उसके बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं होती,तो यह केवल विभागीय लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी विषय बन जाता है, अब देखना यह होगा कि इस बार भी मामला केवल जांच समिति, निरीक्षण और बैठकों तक सीमित रहता है या फिर वास्तव में उन अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है जिनके कार्यकाल में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं,जनता अब आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई और व्यवस्था में वास्तविक सुधार देखना चाहती है।

फोरलेन सड़क के साथ बनेगी मजबूत जल निकासी व्यवस्था,बारिश में जलभराव से मिलेगी राहत

महापौर ने एनएच,पीडब्ल्यूडी और निगम अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की जानकारी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)। शहर में प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर बुधवार को महापौर कक्ष में नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर बनने वाली फोरलेन सड़क, जल निकासी व्यवस्था और निर्माण कार्य की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में रेलवे स्टेशन से गांधी चौक,भारत माता चौक से दरिमा मोड़ तथा लरंगसाय चौक से रिंग रोड तक स्वीकृत फोरलेन सड़क परियोजना पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग

के अधिकारियों ने बताया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। सड़क निर्माण के साथ-साथ दोनों ओर पक्की नालियां भी बनाई जाएंगी, जिससे बरसात के दौरान पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन से गांधी चौक तक जल निकासी के लिए सात क्रॉस ड्रेनेज (क्रॉसिंग) पुलियों का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं भारत माता चौक से दरिमा मोड़ तक चार अतिरिक्त क्रॉसिंग पुलियां बनाई जाएंगी। इन संरचनाओं के बनने से शहर के कई हिस्सों में वर्षों से बनी जलभराव की समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। बैठक में विशेष रूप से मार्डन विहार, होंडा शोरूम, राजमोहिनी भवन और फिजियोथेरेपी अस्पताल के सामने बारिश के दौरान होने वाले जलभराव पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित नालियों और पुलियों के निर्माण के बाद इन क्षेत्रों में पानी जमा होने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। महापौर ने नगर निगम के सभी जोन प्रभारी अभियंताओं को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों का प्रतिदिन भ्रमण करें और जल निकासी,नालियों की सफाई तथा सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि कहीं भी जलभराव या गंदगी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में नगर निगम के कार्यपालन अभियंता संतोष रवि, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हितेंद्र सिंह,नगर निगम के सहायक अभियंता दुश्यंत बजाज सहित उप अभियंता प्रियांका पटेल,निकहत सबरीन, दिलीप कश्यप,रितेश कंवर,प्रेम प्रकाश दुबे,सतीश रवि, राष्ट्रीय राजमार्ग के उप अभियंता राजेंद्र तिग्गा तथा लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता सतीश साहू सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार -2 अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,(छ0ग0)

रा0प्र0क्र0. / अ-6 / 2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रघुनंदन यादब आ. स्व. बाघराम यादव व अन्य, जाति बरगाह, निवासी ग्राम नर्बदापारा, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा ग्राम नर्बदापारा स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 22 कुल रकबा 2.395 70 भूमि के राजस्व अभिलेखो में वर्तमान मृत खातेदार स्व0 बाघराम का नाम विलोपित कराते हुए उनक विधिक वारिशों के नाम पर फौती दर्ज कराने बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 17/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दादा आप प्रस्तुत कर सकते है । समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

अतिरिक्त तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

CMYK

सोशल मीडिया की एक टिप्पणी ने खड़े किए कई सवाल,कहीं अपराध का बचाव तो नहीं बन गई सफाई?

अगर मृतक अपराधी था,तो क्या न्यायालय बंद हो गए थे? पुलिस छुट्टी पर थी या फिर कुछ लोगों ने खुद को कानून का नया अवतार मान लिया?

हत्या के बाद संवेदना नहीं, सफाई क्यों? त्रिपाठी परिवार के सदस्य की फेसबुक पोस्ट ने खड़े किए कई सवाल

क्या किसी को गुंडा बताकर हत्या का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है? फेसबुक पोस्ट पर उठे गंभीर सवाल

फेसबुक पर मृतक का चरित्र चित्रण,समाज पूछ रहा... क्या कानून से ऊपर है निजी फैसला?

सीबीआई जांच की मांग के साथ मृतक पर आरोपों की बौछार,आखिर फेसबुक पोस्ट का मकसद क्या?

हत्या के बाद सोशल मीडिया पर सफाई,क्या जनमत प्रभावित करने की कोशिश?

अगर कोई अपराधी था तो क्या उसे मारने वालों को परमवीर चक्र मिलना चाहिए? फेसबुक पोस्ट ने छेड़ी नई बहस

करो या मरो के दावे से लेकर मृतक के आपराधिक इतिहास तक, फेसबुक पोस्ट ने जांच से पहले ही खड़े कर दिए कई प्रश्न

मृतकों पर आरोप,परिवार का बचाव और सीबीआई जांच की मांग...त्रिपाठी परिवार के सदस्य की फेसबुक पोस्ट से छिड़ी नई बहस

हत्या के बाद सफाई की पटकथा या सच सामने लाने की कोशिश?

त्रिपाठी परिवार के सदस्य की फेसबुक पोस्ट ने खड़े किए कानून,संवेदना और न्याय व्यवस्था पर कई सवाल

अगर कोई गुंडा था तो क्या उसे जिंदा जला देना संविधान का नया अध्याय है?

अंकित त्रिपाठी
त्रिपाठी परिवार के सदस्य

-रवि सिंह-

कोरिया/सोनहत,25 जून 2026 (घटती-घटना)। भूपेश बघेल के पीड़ित परिवार से मिलने की खबर पर दैनिक घटती-घटना की फेसबुक पोस्ट के नीचे आई टिप्पणी बनी चर्चा का विषय,सीबीआई जांच की मांग के साथ मृतक पर गंभीर आरोप,अब सवाल–क्या यह केवल पक्ष रखने का प्रयास है या समाज के सामने एक नई धारणा स्थापित करने की कोशिश? नौगई तिहरे हत्याकांड अब केवल पुलिस विवेचना तक सीमित नहीं रह गया है, यह मामला अब समाज,राजनीति और सोशल मीडिया तीनों के बीच बहस का विषय बन चुका है,एक ओर पुलिस लगातार गिरफ्तारियां कर रही है,दूसरी ओर मृतकों का परिवार निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग कर रहा है,वहीं अब आरोपित पक्ष की ओर से भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखी जाने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पीड़ित परिवार से मुलाकात की खबर जब दैनिक घटती-घटना में प्रकाशित हुई और उसकी कटिंग फेसबुक में डली तब सामान्य प्रतिक्रियाओं के बीच त्रिपाठी परिवार के सदस्य अंकित त्रिपाठी ने एक लंबी सार्वजनिक टिप्पणी लिखी,इस टिप्पणी में उन्होंने स्वयं और अपने परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग की,पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया तथा मृतकों में से एक लल्ला सिंह के संबंध में कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना वाले दिन उनके परिवार के सामने करो या मरो जैसी स्थिति बन गई थी तथा पुलिस को संभावित विवाद की जानकारी होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई,अंकित त्रिपाठी का यह बयान सार्वजनिक है और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है,इसलिए यह केवल एक फेसबुक टिप्पणी नहीं रह जाती,बल्कि एक सार्वजनिक पक्ष बन जाता है,जिस पर समाज और कानून दोनों की दृष्टि से चर्चा होना स्वाभाविक है,लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि टिप्पणी में क्या लिखा गया,बल्कि यह है कि उस टिप्पणी का उद्देश्य क्या प्रतीत होता है? क्या यह केवल सीबीआई जांच की मांग है? क्या यह अपने परिवार का पक्ष रखने का प्रयास है? या फिर यह समाज के सामने मृतकों के प्रति सहानुभूति कम करने वाली एक वैकल्पिक कथा प्रस्तुत करने की कोशिश है? यही वे प्रश्न हैं जो अब चर्चा का विषय बन गए हैं।

क्या अब परमवीर चक्र भी कानून अपने हाथ में लेने वालों को मिलेगा ?

यहीं एक व्यंग्यात्मक लेकिन गंभीर प्रश्न खड़ा होता है,यदि यह मान लिया जाए कि किसी कथित अपराधी के विरुद्ध कानून अपने हाथ में लेना उचित है...यदि यह मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति के बारे में आरोप लगाकर उसकी हत्या के प्रति समाज की संवेदना कम की जा सकती है...तो फिर क्या अगला कदम यह होगा कि ऐसे लोगों को परमवीर चक्र जैसी उपाधियां भी दी जाएं? स्पष्ट है–लोकतंत्र का उत्तर नहीं है,परमवीर चक्र राष्ट्र की रक्षा में अद्वितीय साहस के लिए दिया जाता है,कानून को अपने हाथ में लेने के लिए नहीं,भारत का संविधान बहादुरी का सम्मान अवश्य करता है,लेकिन वह वैधानिक प्रक्रिया से ऊपर किसी भी निजी न्याय व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, इसलिए यदि किसी तर्क का निष्कर्ष यह निकलता है कि कथित अपराधी को जीने का अधिकार नहीं था,तो यह तर्क संविधान की मूल भावना से मेल नहीं खाता।

छह गाड़ियों का दावा–अब पुलिस के सामने नया सवाल...

अंकित त्रिपाठी ने यह भी दावा किया है कि मृतक छह वाहनों में अपने साथियों के साथ गांव पहुंचा था और उन्होंने यह भी कहा है कि घटना में केवल गिरफ्तार लोग ही नहीं,बल्कि गांव के अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए,यदि ऐसा दावा सार्वजनिक रूप से किया गया है,तो अब पुलिस के सामने यह दायित्व भी है कि वह स्पष्ट करे की क्या जांच में छह वाहनों के संबंध में कोई साक्ष्य मिले हैं? क्या सीसीटीवी,मोबाइल लोकेशन या अन्य तकनीकी साक्ष्य इस दावे की पुष्टि करते हैं? क्या जांच एजेंसी इस दिशा में भी काम कर रही है? यदि हां,तो उसे उचित समय पर सार्वजनिक करना चाहिए,यदि नहीं,तो इस दावे का आधार क्या है?

दैनिक घटती-घटना पर लगाए गए आरोपों का जवाब...

अंकित त्रिपाठी ने अपनी टिप्पणी में दैनिक घटती-घटना के समाचारों को एकपक्षीय बताया है,इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि दैनिक घटती-घटना ने अब तक जो भी समाचार प्रकाशित किए हैं,वे उपलब्ध पुलिस जानकारी,घटनास्थल से प्राप्त तथ्यों,जनचर्चा और संबंधित पक्षों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर प्रकाशित किए गए हैं,समाचार प्रकाशित करना और न्यायालय का निर्णय देना दो अलग-अलग विषय हैं,दैनिक घटती-घटना ने किसी को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया है और न ही न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है, यदि किसी पक्ष का संस्करण उपलब्ध होता है,तो पत्रकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप उसे भी स्थान दिया जाता है।

संवेदना किसके लिए...सिर्फ अपने परिवार के लिए या मृतकों के लिए भी ?

हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ खड़ा होता है,यह स्वाभाविक है,लेकिन जब एक जघन्य तिहरा हत्याकांड हुआ हो,तब समाज यह भी देखता है कि क्या सार्वजनिक प्रतिक्रिया में मृतकों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त की गई? या पूरा प्रयास केवल यह सिद्ध करने का रहा कि मृतक कथित रूप से गलत था? यहीं से सामाजिक विमर्श शुरू होता है, संवेदना और सफाई दोनों में बहुत अंतर होता है।

फैसला फेसबुक नहीं...न्यायालय करेगा...

अंकित त्रिपाठी का बयान अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा है और उसमें उठाए गए प्रत्येक तथ्य की जांच होनी चाहिए,यदि पुलिस से चूक हुई है तो उसकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए,यदि घटना में अन्य लोग शामिल थे तो उनकी भी भूमिका सामने आनी चाहिए,यदि मृतक के विरुद्ध शिकायतें थीं तो वे भी जांच के दायरे में आनी चाहिए,लेकिन एक बात उतनी ही स्पष्ट है की किसी व्यक्ति के कथित आपराधिक इतिहास का दावा उसकी हत्या का औचित्य नहीं बन सकता,यदि किसी को लगता है कि किसी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं था,तो फिर लोकतंत्र,संविधान और न्यायालयों का अस्तित्व ही प्रश्नों के घेरे में आ जाएगा,कानून का राज इसी सिद्धांत पर टिका है कि दोषी को सजा अदालत देगी, भीड़ नहीं, और यदि कभी समाज यह मानने लगे कि किसी कथित अपराधी को मारने वालों को सम्मान मिलना चाहिए,तो फिर व्यंग्य में पूछा गया प्रश्न सचमुच डराने लगता है–क्या अगला कदम उन्हें परमवीर चक्र देने की मांग होगा? लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्तर आज भी वही है जो संविधान ने 75 वर्ष पहले दिया था–नहीं, न्याय का मार्ग अदालत से होकर जाता है, किसी व्यक्ति, समूह या सोशल मीडिया की अदालत से नहीं।

मेरे परिवार को करो या मरो की स्थिति में आखिर पुलिस ने क्यों छोड़ा?

अंकित त्रिपाठी का कहना है कि घटना वाले दिन उनके परिवार को **करो या मरो** जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा,उनके अनुसार मृतक लल्ला सिंह ने घटना से पहले मनोज त्रिपाठी को फोन पर धमकी दी थी और इसकी जानकारी पुलिस को भी थी,उनका आरोप है कि संभावित विवाद की सूचना होने के बावजूद पुलिस ने समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण यह जघन्य घटना हुई,अपनी सार्वजनिक टिप्पणी में अंकित त्रिपाठी ने मृतकों में से एक लल्ला सिंह के संबंध में कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं, उन्होंने मृतक के कथित आपराधिक इतिहास, विभिन्न व्यवसायों तथा अन्य गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मामले की सीबीआई जांच होती है तो कई अन्य तथ्य भी सामने आ सकते हैं,साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घटना में केवल गिरफ्तार आरोपियों की ही नहीं,बल्कि गांव के अन्य लोगों की संभावित भूमिका की भी जांच होनी चाहिए,अंकित त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि घटना वाले दिन मृतक छह वाहनों में अपने साथियों के साथ नौगई पहुंचे थे, यदि ऐसा है तो अब यह पुलिस जांच का विषय है कि क्या विवेचना में छह वाहनों के संबंध में कोई साक्ष्य मिले हैं,क्या तकनीकी जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हैं अथवा नहीं,इस संबंध में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आना भी आवश्यक है,लेकिन इसी के साथ एक और प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है,यदि परिवार को वास्तव में जान का खतरा था, तो क्या पुलिस कंट्रोल रूम को तत्काल सूचना दी गई? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी को लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना भेजी गई? क्या अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई? क्या घटना को रोकने के लिए सभी वैधानिक उपाय किए गए? इन प्रश्नों के उत्तर भी उतने ही आवश्यक हैं, क्योंकि भारतीय कानून आत्मरक्षा का अधिकार देता है, लेकिन आत्मरक्षा और प्रतिशोध में स्पष्ट कानूनी अंतर है,यह अंतर जांच और न्यायालय ही तय करेंगे।

मृतक के कथित आपराधिक इतिहास का उल्लेख...क्या इससे हत्या का औचित्य सिद्ध होता है?

अंकित त्रिपाठी ने अपनी टिप्पणी में मृतक लल्ला सिंह के कथित आपराधिक इतिहास का उल्लेख किया है,उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि सीबीआई जांच होने पर बहुत से तथ्य सामने आएंगे, यदि वास्तव में किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामले थे,तो उनकी जांच और सुनवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए,लेकिन यहां मूल प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति का कथित आपराधिक इतिहास उसकी हत्या का कानूनी या नैतिक औचित्य बन सकता है? उत्तर स्पष्ट है–नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है,यह अधिकार किसी व्यक्ति के चरित्र प्रमाणपत्र पर निर्भर नहीं करता,यदि कोई अपराधी है तो उसे अदालत सजा देगी,यदि वह निर्दोष है तो अदालत उसे मुक्त करेगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति या समूह को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह स्वयं अंतिम फैसला सुनाए।

यदि ऐसा तर्क स्वीकार कर लिया जाए तो फिर अदालतों की जरूरत क्या है?

कल्पना कीजिए की आज कोई कहे कि अमुक व्यक्ति अपराधी था, इसलिए उसके साथ जो हुआ वह उचित था,कल कोई दूसरे व्यक्ति के लिए यही तर्क देगा,फिर तीसरा किसी पत्रकार,व्यापारी, डॉक्टर या जनप्रतिनिधि के लिए यही बात कहेगा,यदि समाज इस सोच को स्वीकार कर ले,तो फिर न्यायालयों, पुलिस और संविधान की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी,तब हर व्यक्ति स्वयं जांच अधिकारी भी होगा, अभियोजक भी और न्यायाधीश भी,लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह भीड़ के न्याय को स्वीकार नहीं करता।

एक तरफ नशे के खिलाफ 'ऑपरेशन क्लीन',दूसरी तरफ सवालों की लंबी सूची

- सुपरमैन रंजीत गुप्ता की टीम की लगातार कार्रवाई जारी...कोरिया में महुआ शराब पर भी शिकंजा,क्या कार्रवाई से खत्म होगा पूरा अवैध कारोबार?
- नशीले इंजेक्शन से लेकर महुआ शराब तक अभियान तेज,50 से ज्यादा प्रकरणों के बाद भी सरगुजा संभाग में अवैध नशे का नेटवर्क क्यों सक्रिय?

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा संभागीय आबकारी उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता की टीम लगातार अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नशीले इंजेक्शनों के मामलों में सप्लायरों तक पहुंचने के बाद अब टीम ने कोरिया जिले में महुआ शराब के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। 25 जून को कोरिया जिले के चरचा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए आबकारी उड़नदस्ता टीम ने 21 लीटर महुआ शराब और करीब 250 किलो महुआ लाहन जब्त किया। मामले में पंडोपारा चरचा निवासी दिलमोहन तिर्की को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत जेल दाखिल किया गया। विभाग इसे बड़ी सफलता बता रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा है–क्या कार्रवाई के बाद अवैध नशे का कारोबार वास्तव में खत्म हो रहा है या सिर्फ नए मामलों के रूप में सामने आ रहा है?

मुखबिर से मिली सूचना,घर बना था शराब बनाने का अड्डा : आबकारी विभाग के अनुसार मदिरा दुकान चरचा के निरीक्षण के दौरान टीम को सूचना मिली कि पंडोपारा निवासी दिलमोहन तिर्की अपने घर में महुआ शराब बनाकर बिक्री करता है।

सूचना की पुष्टि के लिए पहले आरोपी के घर से एक लीटर महुआ शराब खरीदी गई। इसके बाद टीम ने दबिश दी। तलाशी के दौरान एक कमरे में महुआ शराब बनाने की व्यवस्था मिली। वहां प्लास्टिक के डिब्बों में करीब 250 किलो महुआ लाहन और 20 लीटर तैयार महुआ शराब बरामद हुई। मौके पर महुआ लाहन नष्ट कर 21 लीटर शराब जब्त की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई पर सवाल नहीं,लेकिन नेटवर्क पर सवाल बरकरार : सुपरमैन रंजीत गुप्ता की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कभी नशीले इंजेक्शन बेचने वालों पर कार्रवाई। कभी सप्लायरों की गिरफ्तारी। कभी अवैध शराब बनाने वालों पर छापेमारी।

लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच जनता का सवाल यह है कि आखिर अवैध नशे का कारोबार बार-बार नए रूप में सामने क्यों आ रहा है?

यदि एक क्षेत्र में कार्रवाई होती है तो दूसरे क्षेत्र में नया मामला सामने आ जाता है। यानी समस्या केवल एक आरोपी तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करती है।

नशीले इंजेक्शन मामले में भी यही सवाल : हाल ही में वाहिद अंसारी, मोशीम अंसारी और लुंड्रा क्षेत्र से कथित नशीले इंजेक्शन सप्लायरों की गिरफ्तारी हुई। सैकड़ों इंजेक्शन जब्त किए गए। आबकारी विभाग ने कार्रवाई को सफलता बताया।

लेकिन अब भी सवाल कायम है कि...

- इन इंजेक्शनों की सप्लाई का मूल स्रोत कौन है?
- बड़े सप्लायर कहां हैं?
- कौन लोग इस कारोबार को आर्थिक रूप से चला रहे हैं?

गढ़वा कनेक्शन और संसाधनों की मजबूरी : सहायक जिला आबकारी अधिकारी सुपरमैन रंजीत गुप्ता ने खुद बताया था कि नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई गढ़वा क्षेत्र से जुड़ी हुई है,लेकिन वहां तक पहुंचने में विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने विभाग के पास सीमित संसाधन,साइबर सेल और तकनीकी सुविधाओं की कमी का भी उल्लेख किया। यहीं से सवाल उठता है कि यदि अवैध नेटवर्क अंतरराज्यीय स्तर पर फैला है तो क्या केवल स्थानीय स्तर की कार्रवाई पर्याप्त होगी? क्या पुलिस, ड्रग विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रणनीति जरूरी नहीं है?

महुआ शराब से लेकर इंजेक्शन तक... चुनौती बड़ी : अवैध शराब और नशीली दवाइयों का कारोबार अलग-अलग जरूर दिखता है,लेकिन दोनों मामलों में एक बात समान है... मांग और सप्लाई का नेटवर्क।

- एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में महुआ शराब का अवैध निर्माण जारी है।
- दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में नशीले इंजेक्शन पहुंच रहे हैं।
- ऐसे में केवल गिरफ्तारियां नहीं बल्कि पूरे सप्लाई सिस्टम पर प्रहार जरूरी माना जा रहा है।

जनता के सवाल...

- क्या गिरफ्तार आरोपियों के पीछे मौजूद लोगों तक जांच पहुंचेगी?
- क्या अवैध कारोबार से जुड़े आर्थिक नेटवर्क की जांच होगी?
- क्या बार-बार सामने आने वाले क्षेत्रों में स्थायी निगरानी व्यवस्था बनेगी?
- क्या आबकारी, पुलिस और ड्रग विभाग मिलकर संयुक्त अभियान चलाएंगे?
- क्या केवल केस दर्ज होंगे या अवैध कारोबार की जड़ पर कार्रवाई होगी?

'गांधी उद्यान बचाओ' की उठी आवाज 5.68 एकड़ जमीन को फिर हरियाली में बदलने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कलेक्ट्रेट के सामने स्थित गांधी उद्यान बना आयोजनों का स्थल,सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा बोले- शहर को चाहिए बच्चों-बुजुर्गों के लिए एक बेहतर पार्क...

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)। शहर के हृदय स्थल में स्थित गांधी उद्यान (कला केंद्र) को उसके मूल स्वरूप में विकसित करने की मांग तेज हो गई है। तरु-नीर समिति के अध्यक्ष, भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर 5.68 एकड़ भूमि को पुनः जनहित के लिए विकसित करने की मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि शासकीय रिकॉर्ड में प्लाट नंबर 508, रकबा 5.68 एकड़ भूमि गांधी उद्यान, नगर पालिका अंबिकापुर के नाम दर्ज है। यह भूमि शासन के निर्देश के बाद वर्ष 1989 में नगर पालिका को गांधी उद्यान के उद्देश्य से हस्तांतरित की गई थी।

जिस उद्देश्य से मिली जमीन,उसी रूप में हो विकास

कैलाश मिश्रा ने कहा कि भूमि हस्तांतरण का उद्देश्य शहरवासियों के लिए एक सुंदर और उपयोगी उद्यान तैयार करना था,लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग प्रदर्शनी,मीना बाजार और अन्य आयोजनों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इसे गांधी उद्यान की मूल भावना से अलग बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस स्थान को फिर से हरियाली और जनसुविधाओं से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर जैसे तेजी से बढ़ते शहर में लोगों को खुले और स्वच्छ वातावरण वाले पार्क की जरूरत है। यहां बच्चों के खेलने, युवाओं के लिए गतिविधियों और बुजुर्गों के टहलने की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए।

लीज अवधि समाप्त,अब नए सिरे से हो पहल

ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि भूमि की लीज अवधि 31 मार्च 2018 तक थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन को जनहित को ध्यान में रखते हुए इस भूमि के उपयोग पर निर्णय लेना चाहिए। 'शहर के बीचों-बीच मौजूद यह जमीन जनता की सुविधा के लिए उपयोग होनी चाहिए' – इस मांग के साथ कैलाश मिश्रा ने कलेक्टर से गांधी उद्यान को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित करने की अपील की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मांग पर क्या कदम उठाता है और वर्षों पुराने गांधी उद्यान को नया स्वरूप मिल पाता है या नहीं।

विधायक निधि से नाली निर्माण या नियमों की अनदेखी?

ग्राम पंचायत एजेंसी, लेकिन निर्माण करा रहे कथित रूप से विधायक के करीबी

इंजीनियर और जनपद को जानकारी नहीं होने का दावा

12 फीट सड़क पर दोनों ओर नाली निर्माण से ग्रामीणों में नाराजगी

पानी निकासी की व्यवस्था नहीं, गुणवत्ता और तकनीकी स्वीकृति पर उठे गंभीर सवाल

गुणवत्ता, तकनीकी स्वीकृति और नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल

-ओंकार पाण्डेय-

सूरजपुर,25 जून 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले के भैयाथान जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत डबरीपारा में विधायक निधि से स्वीकृत लगभग पांच लाख रुपये की लागत से हो रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं,जिस कार्य का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से होना है, उस कार्य को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर पंचायत की बजाय विधायक के करीबी लोगों द्वारा निर्माण कराया जा रहा है,इससे भी बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि संबंधित तकनीकी अमला और जनपद पंचायत के अधिकारियों को भी कथित रूप से निर्माण शुरू होने की जानकारी नहीं थी, यदि यह दावा सही है तो आखिर सरकारी निर्माण कार्य किसकी अनुमति और किस तकनीकी स्वीकृति से प्रारंभ हुआ?

ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 300 मीटर लंबी नाली का निर्माण कराया जा रहा है,जबकि इस कार्य के लिए लगभग पांच लाख रुपये की स्वीकृति मिली है,निर्माण स्थल पर न तो किसी प्रकार का सूचना बोर्ड लगाया गया है और न ही तकनीकी जानकारी सार्वजनिक की गई है, इससे लोगों में यह संशय बढ़ रहा है कि कहीं सरकारी राशि का उपयोग बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए तो नहीं किया जा रहा।

निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत, फिर काम कौन करा रहा है?

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार विधायक निधि से स्वीकृत इस निर्माण कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत है,सामान्यतः ऐसे कार्यों की निगरानी पंचायत, तकनीकी विभाग और जनपद पंचायत के माध्यम से होती है,लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर पंचायत के प्रतिनिधियों की भूमिका गौण है और निर्माण कार्य कथित रूप से विधायक के करीबी लोगों द्वारा कराया जा रहा है, यदि यह आरोप सही है तो कई प्रश्न खड़े होते हैं निर्माण सामग्री कौन खरीद रहा है? मजदूरों का भुगतान कौन कर रहा है? गुणवत्ता की निगरानी कौन करेगा? माप पुस्तिका (एमबी) कौन भरेगा? निर्माण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र कौन देगा? यदि एजेंसी ग्राम पंचायत है तो पंचायत की भूमिका आखिर कहां दिखाई दे रही है?

जनता पूछ रही है...

- ग्राम पंचायत एजेंसी है तो काम कौन करा रहा है?
- इंजीनियर को जानकारी नहीं थी तो निर्माण किसके आदेश पर शुरू हुआ?
- पांच लाख रुपये की लागत का निर्धारण किस आधार पर किया गया?
- पहले से बनी नाली की सफाई क्यों नहीं हुई?
- 12 फीट सड़क पर दोनों ओर नाली बनाने की तकनीकी आवश्यकता क्या थी?
- नाली का पानी आखिर जाएगा कहां?
- क्या किसानों की सहमति ली गई?
- क्या विधायक निधि के उपयोग में सभी नियमों का पालन किया जा रहा है?

12 फीट सड़क पर दोनों ओर नाली, आवागमन कैसे होगा ?

जिस सड़क पर नाली बनाई जा रही है उसकी चौड़ाई लगभग 12 फीट बताई जा रही है,यदि दोनों ओर नाली बन जाती है तो सड़क की उपयोगी चौड़ाई और कम हो जाएगी, ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही गांव में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है,ऐसी स्थिति में दो चारपहिया वाहन एक साथ नहीं निकल पाएंगे, आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या अग्निशमन वाहन के आवागमन में भी कठिनाई हो सकती है, क्या इस पहलू पर किसी तकनीकी अधिकारी ने विचार किया?

पहले से एक नाली मौजूद, फिर दूसरी बनाने की जरूरत क्यों ?

ग्रामीणों के अनुसार सड़क के एक ओर पहले से नाली बनी हुई है,हालांकि वह वर्षों से सफाई नहीं होने के कारण मिट्टी और कचरे से पट चुकी है,ऐसे में ग्रामीण पूछ रहे हैं कि पहले पुरानी नाली की सफाई और मरम्मत क्यों नहीं कराई गई? नई नाली बनाने की आवश्यकता किस आधार पर तय की गई? क्या किसी तकनीकी सर्वे के बाद यह निर्णय लिया गया? या केवल विधायक निधि खर्च करने के उद्देश्य से नया निर्माण शुरू कर दिया गया?

क्या विधायक निधि का उपयोग नियमों के अनुसार हो रहा है ?

विधायक निधि का उद्देश्य जनहित के विकास कार्य कराना है,लेकिन यदि निर्माण कार्य नियमों के विपरीत,बिना तकनीकी स्वीकृति या बिना समुचित निगरानी के कराया जाता है तो इससे निधि के उपयोग पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है,यह भी जांच का विषय है कि क्या कार्य प्रारंभ करने से पहले सभी प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां प्राप्त की गई थीं? क्या निर्माण एजेंसी की भूमिका का पालन हो रहा है? क्या भुगतान नियमानुसार होगा?

ग्राम पंचायत की हो रही किरकिरी...

इस पूरे मामले में सबसे अधिक सवाल ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं,सरकारी रिकॉर्ड में एजेंसी पंचायत है,लेकिन यदि निर्माण कार्य का संचालन कोई अन्य कर रहा है तो भविष्य में किसी भी तकनीकी या वित्तीय अनियमितता की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका स्पष्ट होना आवश्यक है।

ग्रामीणों की मांग...पहले जांच...फिर निर्माण...

स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने मांग की है कि जब तक पूरे मामले की तकनीकी जांच नहीं हो जाती, तब तक निर्माण कार्य रोका जाए, उनका कहना है कि यदि बाद में डिजाइन या जल निकासी में त्रुटि सामने आती है तो सरकारी धन भी व्यर्थ जाएगा और ग्रामीणों को भी परेशानी होगी।

जांच से ही दूर होंगे संदेह...

डबरीपारा का यह मामला केवल नाली निर्माण का नहीं है,बल्कि सरकारी धन के उपयोग,पंचायत की जवाबदेही,तकनीकी स्वीकृति और विकास कार्यों में पारदर्शिता से जुड़ा मामला बन गया है, यदि ग्रामीणों के आरोप सही हैं तो यह गंभीर प्रशासनिक विषय है,वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो संबंधित विभाग को भी तथ्य सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,अब जिला प्रशासन,जनपद पंचायत और तकनीकी विभाग की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर यह स्पष्ट करें कि निर्माण कार्य सभी नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं,यदि कहीं भी प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए, ताकि विधायक निधि जैसी जनहित की योजनाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।

इंजीनियर को जानकारी नहीं, फिर तकनीकी स्वीकृति किसने दी ?

स्थानीय लोगों का दावा है कि संबंधित उप अभियंता (इंजीनियर) को भी कार्य प्रारंभ होने की जानकारी नहीं थी,यदि ऐसा है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है, सरकारी निर्माण कार्य बिना तकनीकी स्वीकृति और ले-आउट के प्रारंभ नहीं किए जा सकते,ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्या निर्माण स्थल का तकनीकी निरीक्षण हुआ? क्या ले-आउट जारी किया गया? क्या ड्राइंग के अनुसार कार्य हो रहा है? क्या कार्य प्रारंभ करने की अनुमति संबंधित इंजीनियर ने दी? यदि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ तो निर्माण की गुणवत्ता और भुगतान दोनों सवालों के घेरे में आ सकते हैं।

नाली बनेगी...लेकिन पानी जाएगा कहां ?

निर्माण कार्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल जल निकासी को लेकर उठ रहा है, लगभग 300 मीटर लंबी नाली बनाई जा रही है, लेकिन उसके बाद पानी किस दिशा में छोड़ा जाएगा? क्या किसी नाले से इसे जोड़ा जाएगा? क्या किसी किसान के खेत में पानी छोड़ा जाएगा? यदि ऐसा होगा तो संबंधित भूमि स्वामी की सहमति ली गई है या नहीं? ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है, ऐसे में आशंका है कि बरसात के समय यह नाली स्वयं विवाद का कारण बन सकती है।

बिना सहमति के निर्माण का आरोप

स्थानीय ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि नाली निर्माण से पहले उनसे कोई सहमति नहीं ली गई,न तो ग्राम सभा में व्यापक चर्चा हुई और न ही प्रभावित लोगों की राय ली गई,यदि यह आरोप सही है तो पंचायत राज अधिनियम की भावना पर भी प्रश्न उठते हैं,ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में स्थानीय लोगों की सहभागिता और सहमति महत्वपूर्ण मानी जाती है।

गुणवत्ता कौन देखेगा ?

निर्माण कार्य में तकनीकी अधिकारी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, यदि इंजीनियर की जानकारी के बिना निर्माण प्रारंभ हुआ है, जैसा कि ग्रामीण दावा कर रहे हैं, तो गुणवत्ता की निगरानी कौन करेगा? क्या निर्माण सामग्री मानक के अनुरूप है? क्या सीमेंट, गिट्टी और रेत का अनुपात सही रखा जा रहा है? क्या नाली की गहराई और चौड़ाई स्वीकृत डिजाइन के अनुसार है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर तकनीकी विभाग को देना होगा।

मेहनत ही सफलता की कुंजी : जब कलेक्टर ने छात्रा को सिखाया यूपीएससी का सक्सेस मंत्र

आठवीं की छात्रा ने पूछा...यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? कलेक्टर ने कहा... बड़े सपने देखो,मेहनत से मिलेगा मुकाम

कोरिया,25 जून 2026(घटती-घटना)। जिले के सोनहत विकासखंड के रामगढ़ कन्या आश्रम शाला में कक्षा आठवीं की छात्रा के सवाल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। छात्रा ने कलेक्टर रोक्तिमा यादव से पूछा...यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? छात्रा के बड़े सपने और आत्मविश्वास को देखकर कलेक्टर ने उसकी सराहना की और उसे अभी से लक्ष्य तय कर मेहनत करने की प्रेरणा दी।

नियमित पढ़ाई और सामान्य ज्ञान पर दिया जोर

कलेक्टर ने छात्रा को बताया कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत बड़े लक्ष्य से होती है। उन्होंने कहा कि अभी से नियमित अध्ययन की आदत डालें, सभी विषयों की मजबूत समझ बनाएं और सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दें। समाचार पत्र पढ़ने,समसामयिक घटनाओं की जानकारी रखने और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अध्ययन करने की भी सलाह दी।

बच्चों से संवाद कर बढ़ाया आत्मविश्वास

स्कूल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई,भविष्य की योजनाओं और विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों को स्पष्ट लक्ष्य बनाकर अनुशासन और मेहनत के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि सफलता निरंतर प्रयास और सीखने की इच्छा से मिलती है।

छात्रा ने सुनाया 26 का पहाड़ा, तो छात्रा को मिली शाबाशी...

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने सोनहत स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय और रामगढ़ माध्यमिक विद्यालय का भी जायजा लिया। कक्षा तीसरी की छात्रा ने आत्मविश्वास के साथ 26 का पहाड़ा सुनाया,जिस पर कलेक्टर ने उसकी प्रशंसा की। बच्चों ने कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा दिखाई।

मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता भी जांची

कलेक्टर ने कन्या आश्रम शाला और छात्रावास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने भोजन, पेयजल, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन कर उन्होंने भोजन की गुणवत्ता जांची और अधिकारियों को पौष्टिक भोजन व बेहतर व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए।

ग्रामीण बच्चों को दिया बड़े सपने देखने के संदेश

कलेक्टर ने कहा कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। सही दिशा, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। कलेक्टर के इस प्रेरणादायी संवाद से विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार हुआ।

CMYK

हिंदी फिल्में तुम्हारे लिए नहीं हैं...कॉकटेल 2 में रश्मिका मंदाना की एक्टिंग देख शोभा डे हुईं हैरान

जानी-मानी ऑथर शोभा डे ने रोम-कॉम ड्रामा कॉकटेल 2 देखने के बाद फिल्म और कलाकारों की परफॉर्मेंस के बारे में अपना रिव्यू शेयर किया है।

शाहिद कपूर,कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से ही अच्छी कमाई कर रही है। 6 दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया, लेकिन फिल्म को रिव्यू मिला-जुला मिल रहा है।

हाल ही में जानी-मानी ऑथर शोभा डे ने होमी अदजानिया निर्देशित कॉकटेल 2 देखी और सोशल मीडिया पर अपना रिव्यू शेयर किया है। उन्होंने पहली वाली कॉकटेल (2012) वाली मूवी को ज्यादा बेहतर बताया है।

शोभा डे ने किया कॉकटेल 2 का रिव्यू

शोभा डे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कॉकटेल 2 का रिव्यू शेयर किया। उन्होंने कहा,कॉकटेल 2 देखकर आई हूं। खैर,यह कॉकटेल1 जैसी तो बिल्कुल नहीं है। वह कॉकटेल क्या थी और यह क्या है। मुझे लगता है कि इससे उबरने के लिए मुझे पांच नेग्रोनी (एक तरह की ड्रिंक) पीनी पड़ेंगी। इसका ना सिर है ना पैर है। कुछ भी नहीं है। कहानी बेतुकी है।

रश्मिका को लेकर बिगड़े बोल

शोभा डे ने फिल्म को बेतुका बताने के साथ-साथ स्टार्स की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा,शाहिद तुम्हें नए हेयरकट की जरूरत है,हालांकि तुम फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा हो। लेकिन असली स्टार तो सिसिली है। काश सिसिली को और ज्यादा दिखाया जाता। रश्मिका मंदाना,मुझे माफ करना लेकिन हिंदी फिल्में तुम्हारे लिए नहीं हैं। कृति, तुम बहुत अच्छी लग रही हो,तुम्हारा फिगर जबरदस्त है। सच कहूं तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है।

पहली वाली से नहीं फिल्म की तुलना

शोभा डे ने आगे कहा, लेकिन क्या कहानी थोड़ी और गहरी और अर्थपूर्ण हो सकती थी? दो औरतें शाहिद के लिए लड़ रही हैं और फिर वह उन्हें लेक्चर देता है। फिर शाहिद की सबसे अच्छी बात सुनने को मिलती है, जब वह कहता है,प्यार ऐसी चीज है जिसका आप कुछ दिनों तक मजा ले सकते हैं,असल में प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सब बनावटी ज्ञान से भरा है। एकदम घिसी-पिटी बातें। बीच-बीच में अच्छे मजाक भी हैं। लेकिन इसकी तुलना कॉकटेल से करने की कोशिश भी मत करना। मैं पांच नेग्रोनी ड्रिंक्स इंतजार कर रही हैं। यह रहा मेरा छोटा सा रिव्यू।

रिया चक्रवर्ती का दर्द : काम बंद,भाई बेरोजगार

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में अपने करियर के उस मुश्किल दौर को याद किया जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। एक टॉक शो में बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि 2020 के बाद उनके लिए हालात काफी बदल गए थे और उन्हें लगातार प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे।

इसी दौरान उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को भी नौकरी के अवसर नहीं मिल पा रहे थे, जिससे दोनों के सामने आर्थिक और पेशेवर चुनौतियां खड़ी हो गई थीं। रिया चक्रवर्ती हाल ही में नेहा धूपिया और अंगद बेदी के यूट्यूब टॉक शो 'डबल डेट' में अपने भाई के साथ नजर आईं। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया और व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन को संभालने की कोशिश की। इसी दौर में रिया और शोविक ने मिलकर 'चैप्टर 2' नाम का बिजनेस शुरू किया। रिया ने बताया कि शुरुआत में दोनों के लिए साथ काम करना आसान नहीं था। कई बार छोटी-छोटी बातों पर बहस बढ़ जाती थी और तनाव की स्थिति बन जाती थी। हालांकि समय के साथ दोनों ने अपने काम और जिम्मेदारियों को समझा और चीजें धीरे-धीरे बेहतर होने लगीं। रिया ने कहा कि वह कंपनी में अकाउंट्स और कंप्लायंस से जुड़े काम देखती हैं, जबकि शोविक ऑपरेशनल और अन्य प्रबंधन कार्य संभालते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बड़े भाई-बहन के रिश्ते के साथ बिजनेस चलाना एक अलग अनुभव है, जिसमें कई बार मतभेद भी होते हैं, लेकिन समय के साथ संतुलन बन गया है। बातचीत के दौरान रिया ने एक मजेदार किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वह अपने बिजनेस का नाम 'चुड़ैल का बदला' रखना चाहती थीं। उन्हें यह नाम दिलचस्प और अलग लगा था और वह इससे जुड़े मर्चेंडाइज और टी-शर्ट्स तक बनाने की सोच रही थीं, लेकिन परिवार और टीम के अन्य लोग इस नाम के खिलाफ थे।

मैं अपनी शर्ट उतार...डांस की रिहर्सल नहीं करते सलमान खान,स्टेप्स भूल जाने पर अपनाते हैं खास तरीका

विंदू दारा सिंह ने सलमान खान के डांस स्टाइल का खुलासा किया है, बताया कि भाईजान बिना ज्यादा प्रैक्टिस के भी आसानी से स्टेप्स सीख लेते हैं।

सलमान खान को बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में गिना जाता है। भाईजान की फैन फॉलोविंग उनकी अगली फिल्म का भविष्य तय करती है। इसके अलावा उनके डांस के भी खूब चर्चे होते हैं। सलमान खान को बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में भले न गिना जाता हो, लेकिन एक्टर विंदू दारा सिंह के मुताबिक इसका टैलेंट से कोई खास लेना-देना नहीं है।

सलमान खान नहीं करते डांस प्रैक्टिस

सलमान खान ने ओ ओ जाने जाना (प्यार किया तो डरना क्या),जीने के हैं चार दिन (मुझसे शादी करोगी) और जुम्मे की रात (किक) जैसे कई ब्लॉकबस्टर गानों में अपनी बॉडी का प्रदर्शन किया। सुपरस्टार के साथ कई फिल्मों में काम करने के अपने अनुभव को याद करते हुए, विंदू ने बताया कि सलमान डांस स्टेप्स की बहुत कम रिहर्सल करते हैं और फिर भी उन्हें बहुत आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं।

मास्टर को देखते ही देने लग जाते टेक

न्यूज 18 के यूट्यूब चैनल से बात करते हुए विंदू ने कहा कि सलमान में तुरंत कोरियोग्राफी सीखने की नेचुरल आदत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर एक्टर रिहर्सल के लिए समय दें, तो वह इंडस्ट्री के कई बेहतरीन डांसर्स से भी बेहतर डांस कर सकते हैं। विंदू ने कहा,वह आते हैं, बैठते हैं और पूछते हैं कि उन्हें क्या करना है। फिर, डांस मास्टर उन्हें स्टेप्स करके दिखाते हैं। वह तुरंत टेक देना शुरू कर देते हैं। दूसरे लोग रिहर्सल में 20 दिन लगाते हैं, वे मुश्किल स्टेप्स की प्रैक्टिस करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं। उन्होंने आगे कहा-सलमान खान बस देखते हैं,प्रैक्टिस नहीं करते। तो सोचिए कि उन्हें यह कितनी आसानी से आ जाता है। उनकी याददाश्त कितनी तेज है और वह कितने टैलेंटेड हैं। अगर वह प्रैक्टिस करें,तो इंडस्ट्री में उनसे बेहतर कोई डांस नहीं कर पाएगा।

विंदू ने बताया लाइव इवेंट का एक किस्सा

विंदू ने कहा कि सलमान प्रैक्टिस करके कई दिनों तक डांस स्टेप्स नहीं सीखते थे वो सिर्फ ऑन स्पॉट प्रैक्टिस करते हैं। विंदू ने मुझसे शादी करोगी की शूटिंग के दौरान की एक याद भी शेयर की, जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी और सलमान को दिल्ली में एक लाइव इवेंट में परफॉर्म करना था। उन्होंने बताया कि कोरियोग्राफर ने लंच ब्रेक के दौरान रिहर्सल के लिए समय मांगा। सलमान ने एक बार कोरियोग्राफी देखी और फिर टीम से जाने के लिए कहा। विंदू ये देखकर बहुत हैरान हुए कि सलमान ने सिर्फ एक बार परफॉर्म किया और इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उनसे पूछा,अगर आप स्टेप्स भूल गए तो? सलमान ने जवाब दिया कि तब वह बस अपनी शर्ट उतार देंगे।

8 साल बाद भी बरकरार है हरियाणवी गाने का क्रेज

हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी का मशहूर गाना 'तेरी अखियां का यो काजल' आज भी लोगों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता बनाए हुए है। रिलीज के लगभग 8 साल बाद भी इस गाने का क्रेज कम नहीं हुआ है और यह यूट्यूब पर लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। यह गाना उन चुनिंदा हरियाणवी गानों में शामिल है,जिसने क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई। यह गाना उस समय रिलीज हुआ था जब हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही थी,लेकिन इस गाने ने उस दौर में भी अलग जगह बनाई। सपना चौधरी का देसी अंदाज, सादगी भरा लुक और दमदार डांस परफॉर्मेंस ने दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। गाने में उनकी परफॉर्मेंस इतनी प्रभावशाली थी कि यह सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो गया। इस गाने ने न केवल दर्शकों के दिलों में जगह बनाई बल्कि सपना चौधरी के करियर में भी बड़ा बदलाव लाया। इससे पहले वह हरियाणा में स्टेज शो के लिए जानी जाती थीं, लेकिन इस गाने की सफलता के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। 'तेरी अखियां का यो काजल' ने उन्हें हरियाणवी मनोरंजन की पहचान से निकालकर एक बड़ी पॉपुलर आर्टिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया। गाने की खासियत इसकी सरलता और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ संगीत है। इसमें न तो अत्यधिक आधुनिक सेटअप है और न ही भारी-भरकम तकनीक, फिर भी इसका असर दर्शकों पर गहरा पड़ा। यही वजह है कि यह गाना लंबे समय तक लोगों की प्लेलिस्ट में बना रहा। कई स्टेज शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी यह गाना आज तक बजाया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस गाने की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। समय-समय पर लोग इसके वीडियो क्लिप्स और डांस परफॉर्मेंस शेयर करते रहते हैं। कई बार बॉलीवुड और खेल जगत से जुड़े लोग भी इस गाने पर डांस करते नजर आए हैं,जिससे इसकी पहुंच और भी बढ़ गई है। यूट्यूब आंकड़ों के अनुसार, इस गाने ने अब तक 664 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं। यह आंकड़ा किसी भी हरियाणवी गाने के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। इस स्तर की लोकप्रियता यह दर्शाती है कि कंटेंट यदि दर्शकों से जुड़ जाए तो वह लंबे समय तक टिक सकता है।

अमिताभ बच्चन पर पान गिरने के बाद क्या हुआ था...

हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस बिंदु ने फिल्मों में 'वैम्प' के किरदारों से अपनी खास पहचान बनाई है। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उस दौर के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर की है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपने फिल्मी सफर से जुड़ा एक दिलचस्प और मजेदार किस्सा साझा किया, जिसमें अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक पुराना वाकया सामने आया। बिंदु ने बताया कि एक बार शूटिंग के दौरान वह और अमिताभ बच्चन फिल्म की यूनिट के साथ ऋषिकेश गए थे। शूटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग देहरादून के एक होटल में खाना खाने पहुंचे। वहां से लौटते समय गाड़ी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे वह आज भी नहीं भूल पाईं। एक्ट्रेस ने बताया कि उस समय वह पान खा रही थीं और गाड़ी की खिड़की के पास बैठी थीं। उन्होंने हवा लेने के लिए अपना चेहरा खिड़की से बाहर निकाला और उसी दौरान उन्होंने पान थूक दिया। दुर्भाग्यवश वह पान सीधे अमिताभ बच्चन की शर्ट पर गिर गया। इस घटना को याद करते हुए बिंदु ने कहा कि उस पल वह बेहद शर्मिंदा हो गई थीं और तुरंत उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी मांगी। हालांकि, बिग बी ने उस समय इस बात को लेकर कोई नाराजगी नहीं दिखाई और पूरे मामले को हल्के में ले लिया। बिंदु के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने उस समय कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन बाद में वह इस घटना को लेकर मजाक में उनकी टांग खींचते रहते थे। इस किस्से को बिंदु ने हंसते हुए साझा किया और बताया कि उस दौर में शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों के बीच काफी अपनापन और हल्के-फुल्के मजाक का माहौल रहता था। बिंदु का यह किस्सा दर्शाता है कि फिल्मी दुनिया में बड़े कलाकारों के बीच भी कई ऐसे मजेदार और अनोखे अनुभव होते हैं, जो आज भी यादगार बने रहते हैं। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार का शांत और समझदार रवैया भी इस घटना को और दिलचस्प बना देता है। इस तरह बिंदु का यह पुराना किस्सा एक बार फिर दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और लोग इसे बड़े चाव से सुन और पढ़ रहे हैं।

खेल समाचार

इंडिया का खिलाड़ी ही टीम इंडिया से लेगा टक्कर

भारत के खिलाफ टी 20 सीरीज के लिए जय मूंदड़ा को आयरलैंड टीम में जगह मिली है। 29 साल के जय का जन्म भारत में हुआ है और 2021 में वह पढ़ाई करने आयरलैंड गए थे...

नई दिल्ली,25 जून 2026। भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ शुक्रवार से टी20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के लिए आयरलैंड टीम की घोषणा भी हो चुकी है। आयरलैंड के कई प्रमुख खिलाड़ी चोटिल चल रहे हैं। इसी वजह से टीम में युवा नामों को शामिल किया गया है। इसमें एक नाम जय मूंदड़ा का भी है। 29 साल के जय ऑलराउंडर हैं। वह बाएं हाथ से गेंदबाजी और बाएं हाथ से ही बल्लेबाजी करते हैं।

भारत में हुआ है जय मूंदड़ा का जन्म

जय मूंदड़ा राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म भी यहीं हुआ है। वह 2021 में एम टेक की डिग्री लेने के लिए स्टूडेंट वीज पर आयरलैंड गए थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह वहां नौकरी करने लगे। इस दौरान क्रिकेट भी खेला करते थे। उन्हें 2025 में आयरलैंड की नागरिकता मिली और अब उन्होंने इंटरनेशनल टीम में जगह भी मिल गई है।

जय मूंदड़ा के परिवार में खुशी की लहर

परिवार वालों के मुताबिक जय का सिलेक्शन उनकी आक्रामक बॉलिंग और शानदार बैटिंग के दम पर हुआ है। एएनआई से बात करते हुए उनकी छोटी बहन मानसी ने कहा,मैं बहुत खुश हूं कि मेरे भाई का सपना सच हो गया है। वह बचपन से ही क्रिकेट खेल रहा है। मैंने अपने भाई से बात की। वे और हम सभी बहुत खुश हैं। वहीं उनकी मांविद्या मूंदड़ा ने कहा-हर कोई बहुत खुश है। उनका बचपन का सपना सच हो रहा है। लोग फोन कर रहे हैं और मिलने आ रहे हैं। हम सभी उनके लिए बहुत उत्साहित हैं। वह पढ़ाई कर रहा था और फिर नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान हमेशा क्रिकेट पर ही रहा। उन्होंने कड़ी मेहनत की है और चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

नाइट राइडर्स पहली बार नए ग्राउंड पर खेलेंगे मैच

लॉस एंजिल्स ,25 जून 2026। नाइट राइडर्स 1 जुलाई को पोमोना के नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में वाशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। यह लॉस एंजिल्स में खास तौर पर बनाए गए स्टेडियम में पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत होगी और यूएसए में खेल को बड़े पैमाने पर विकसित करने की फ्रेंचाइजी की कोशिश में एक अहम कदम होगा। यह मैच उस सफर का नतीजा है जो अप्रैल में शुरू हुआ था, जब यूएसए और फेयरप्लेक्स ने नए वेन्यू का काम शुरू किया था। नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड में 1 जुलाई से 5 जुलाई तक एमएलसी मैच खेले जाएंगे, जिससे लॉस एंजिल्स इलाके में वर्ल्ड क्लास टी 20 क्रिकेट देखने को मिलेगा। लॉस एंजिल्स में एक खास जगह बनाकर, नाइट राइडर्स ग्रुप इस इलाके को देश में खेल के भविष्य के हब के तौर पर स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। नया मैदान लॉस एंजिल्स के फैंस को दुनिया के कुछ सबसे रोमांचक खिलाड़ियों के साथ लाइव प्रोफेशनल क्रिकेट देखने का मौका देता है,साथ ही इस इलाके में वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी रखता है।

पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया,रोनाल्डो ने दागे 2 गोल

नईदिल्ली,25 जून 2026। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप-के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। टीम की जीत के हीरो क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे, जिन्होंने 6वें और 39वें मिनट में गोल दागे। नूनो मेंडिस ने 17वें मिनट में और राफेल लेओ ने 87वें मिनट में गोल किया। वहीं, 60वें मिनट में अब्दुवोहिद नेमातोव के ओन गोल ने उज्बेकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दीं। आइए मैच में बने प्रमुख रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

रोनाल्डो ने मैच में एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। 41 वर्षीय यह खिलाड़ी 6 विश्व कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना। 2018 विश्व कप उनके लिए सबसे यादगार रहा था, जहां उन्होंने 4 गोल किए थे। रोनाल्डो (41 साल 138 दिन) 40 वर्ष की उम्र पार करने के बाद विश्व कप में गोल करने वाले केवल दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि कैमरून के रोजर मिला ने 1994 विश्व कप में हासिल की थी।

रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अपना विश्व कप गोलों का आंकड़ा 10 तक पहुंचा दिया और महान फुटबॉलर यूसेबियो के 9 गोलों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यूसेबियो का यह कीर्तिमान करीब 60 वर्षों तक अटूट रहा था। अब रोनाल्डो ने उनका ये बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। इस सूची में पाउलेटा 4 गोल के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

फीफा विश्व कप 2026: क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराया

नईदिल्ली,25 जून 2026। फीफा विश्व कप 2026 में क्रोएशिया फुटबॉल टीम ने पनामा फुटबॉल टीम को 1-0 से हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की। क्रोएशिया की ओर से आंटे बुदिमिर ने इकलौता गोल किया,जो निर्णायक साबित हुआ। यह पनामा की मौजूदा टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार साबित हुई। इस शिकस्त के साथ ही पनामा की टीम के राउंड ऑफ-32 में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अपने आखिरी ग्रुप मैच में पनामा को इंग्लैंड से भिडना है। पहले हाफ में पनामा ने आक्रामक शुरुआत की,जिसमें क्रोएशिया की टीम दबाव में नजर आई। पनामा की मजबूत रक्षापंक्ति ने क्रोएशिया के इवान पेरिसिच और लुका मोड्रिच जैसे अनुभवी खिलाडियों के आक्रमण को रोका। इसी बीच शुरुआत में मैच धीमा और कम मौकों वाला रहा। मैच के 24वें मिनट में क्रिस्टियन मार्टिनेज ने फ्रीकिक हासिल की,जिसका वह फायदा नहीं उठा सके। लगातार प्रयासों के बीच पहला हाफ गोलरहित रहा।

दुर्ग में 4 कोचिंग सेंटर सील

62 को नोटिस,लखनऊ अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन

दुर्ग,25 जून 2026। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुई दर्दनाक अग्नि दुर्घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक जांच अभियान शुरू किया है। दुर्ग,बिलासपुर और रायपुर जैसे प्रमुख शहरों में पुलिस, एसडीआरएफ और नगर निगम की संयुक्त टीमों ने छापेमारी कर संस्थानों की सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान जो तथ्य सामने आए,वे चौंकाने वाले हैं। जांच में अधिकांश सेंटरों में फायर सेफ्टी उपकरणों का अभाव, आपातकालीन निकास द्वारों की कमी और बिल्डिंग परमिशन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। प्रशासन की इस कठोर कार्रवाई ने कोचिंग संचालकों में हड़कंप मचा दिया है।

दुर्ग में 62 सेंटरों को नोटिस कई प्रमुख संस्थान सील

दुर्ग जिले के भिलाई स्थित न्यू सिविक सेंटर, जहाँ 100 से अधिक कोचिंग सेंटर संचालित हैं, वहां पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। जांच में यह पाया गया कि सुरक्षा मानकों का पालन करने में एक भी संस्थान पूर्णतः सक्षम नहीं था। नियमों की गंभीर अनदेखी के चलते रामा कोचिंग, कैड एकेडमी, मोशन कोटा स्टडी सर्किल और वेदांतु जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को प्रशासन ने तत्काल सील कर दिया। वहीं,अन्य 62 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया गया है। गौरतलब है कि कई सेंटरों में आग बुझाने वाले उपकरण एक्सपायर हो चुके थे और भवन के भीतर से बाहर निकलने का केवल एक ही संकरा रास्ता था, जो किसी भी आपात स्थिति में छात्रों की जान जोखिम में डाल सकता है।

बिलासपुर और रायपुर में भी कड़ा निरीक्षण अभियान

बिलासपुर में भी प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए छह कोचिंग संस्थानों की जांच की, जिनमें से पांच में सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं मिले। नियमों का घोर उल्लंघन पाए जाने पर 'उड़ान एकेडमी' को तुरंत सील कर दिया गया। उधर, रायपुर में भी प्रशासन की टीम ने अनअकैडमी, विद्यापीठ और एलन जैसे बड़े संस्थानों का निरीक्षण किया, जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। हालांकि, अकादजा, आरसीसी एकेडमी, आभा लाइब्रेरी और टुटेजा एकेडमी में फायर एनओसी और आपातकालीन निकास से जुड़ी कमियां मिलने पर उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

छात्रों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की चिंता और भविष्य की राह

निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा के नाम पर छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कई स्थानों पर तो जगह इतनी कम थी कि सीढ़ियां बेहद पतली बनी हुई थीं, जहाँ से एक बार में एक ही छात्र गुजर सकता है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संस्थानों ने अग्नि सुरक्षा मानकों और भवन अनुमतियों की कमियों को दूर नहीं किया, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और संस्थानों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके और भविष्य में लखनऊ जैसी किसी भी त्रासदी को टाला जा सके।

फायर एक्स्टिंग्विशर एक्सपायर मिले...

कहीं फायर एक्स्टिंग्विशर एक्सपायर मिले तो कहीं उन्हें सही तरीके से लगाया ही नहीं गया था। टीम ने कोचिंग सेंटर्स में इमरजेंसी एग्जिट की भी जांच की, लेकिन किसी भी संस्थान में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं मिला। कई जगह बिल्डिंग के भीतर आने-जाने का केवल एक ही रास्ता था।

पतली गली में बनी सीढ़ियां,इमरजेंसी में कूदना ही ऑप्शन

इसके अलावा कुछ सेंटर्स में स्टूडेंट्स की संख्या के मुकाबले जगह भी बेहद कम पाई गईं। कई ऐसे कोचिंग भी मिले जहां इतनी पतली सीढ़ियां बनी थी कि वहां से एक बार में एक ही स्टूडेंट्स चढ़ सकता है। अगर कभी इस तरह की अनहोनी यहां होती है तो छात्रों को उंची बिल्डिंग से कूदना ही एकमात्र विकल्प बचेगा।

एसी कंप्रेसर फटने से पिता की मौत,बेटा गंभीर,आधी रात को मची अफरा-तफरी

रायगढ़,25 जून 2026। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले स्थित आईटीआई कॉलोनी में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर में लगे विंडो एसी के कंप्रेसर में अचानक हुए तेज धमाके से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसे में आईटीआई कॉलोनी निवासी पुरुषोत्तम पटेल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं उनका बेटा राजवीर पटेल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया,जहां उसका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एसी कंप्रेसर में विस्फोट के बाद घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि विंडो एसी के सामने खड़ी दो मोटरसाइकिलें भी उसकी चपेट में आ गईं और पूरी तरह जलकर खाक हो गईं। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना की सूचना मिलते ही चक्रधरनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और तकनीकी कारणों का भी पता लगाया जा रहा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

स्वास्थ्य सेवाओं और किसानों के लिए खाद-बीज उपलब्धता पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर,25 जून 2026। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान जनस्वास्थ्य, चिकित्सा अधोसंरचना, औषधि एवं उर्वरक क्षेत्र सहित विभिन्न विभागीय और समसामयिक विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। विशेष रूप से दूरस्थ, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को मजबूत बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर उपचार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं अपने ही राज्य में उपलब्ध हों। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि और उर्वरक क्षेत्र से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी कि राज्य में किसानों को खाद और बीज की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा खरीफ सीजन के दौरान आवश्यक कृषि आदानों की आपूर्ति सुचारु रूप से बनी रहे। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि खाद वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी अथवा लापरवाही को कतई बर्दाश्त न किया जाए। साथ ही गांव-गांव अभियान चलाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने तथा नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी अवगत कराया कि राज्य सरकार नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। किसानों को इनके लाभों की जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि खेती में उत्पादन क्षमता बढ़े, लागत कम हो और कृषि अधिक लाभकारी बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के पूर्ण सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और जनकल्याण के क्षेत्रों में विकास को नई गति देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, किसानों के हित में उठाए जा रहे कदमों तथा जनकल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

बद्रीनारायण मीणा बने बस्तर रेंज के नए आईजी

रायपुर,25 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बद्रीनारायण मीणा (बैच 2004) को बस्तर रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया है। उनकी नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार, बद्रीनारायण मीणा अब बस्तर रेंज में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति को बस्तर क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले आईपीएस बद्रीनारायण मीणा दुर्ग रेंज के आईजी और एसएसपी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। 2004 बैच के इस आईपीएस अधिकारी ने बिलासपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी) के रूप में भी सेवाएं दी हैं। इससे पहले सुंदरराज पी बस्तर रेंज में आईजी के पद पर तैनात थे। वे करीब पांच साल तक बस्तर में आईजी रहे। अब उन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर एनआईए में आईजी बनाया गया है। उनकी जगह बद्रीनारायण मीणा को बस्तर रेंज का नया आईजी बनाया गया है। बद्रीनारायण मीणा छत्तीसगढ़ कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से वे राजस्थान के जयपुर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता जनगणना विभाग में नौकरी करते थे। बद्री मीणा ने अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई जयपुर में ही पूरी की। उन्होंने सनफ्लावर पब्लिक स्कूल से दसवीं और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोद्दार से बारहवीं की पढ़ाई की। इसके बाद राजस्थान कॉलेज, जयपुर से वर्ष 2000 में बीए की डिग्री हासिल की।

सीबीएसई का फैसला...अब रीजनल ऑफिस में आंसर शीट चेक होगी,वेरिफिकेशन के बाद भी अंक नहीं बदलने वाले छात्रों को मिलेगा अतिरिक्त मौका

रायपुर,25 जून 2026। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर यदि किसी छात्र के मन में अब भी संदेह है, तो उसके लिए बोर्ड ने पहली बार एक नई व्यवस्था लागू की है। अब वे छात्र, जिन्होंने अंकों के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया था लेकिन जांच के बाद भी उनके अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, सीधे सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर अपनी उत्तर पुस्तिका की फिजिकल जांच करवा सकेंगे। सीबीएसई ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड के मुताबिक यह सुविधा सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं होगी। इसका लाभ केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, जिनके वेरिफिकेशन का परिणाम 'नो चेंज' रहा है। बोर्ड जल्द ही क्षेत्रीय कार्यालयों में उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए विस्तृत शेड्यूल और प्रक्रिया जारी करेगा। यह व्यवस्था पहली बार लागू की गई है। इससे पहले वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों के पास उत्तर पुस्तिका की फिजिकल जांच कराने का कोई विकल्प नहीं होता था।

सचिन पायलट बोले...बीजेपी अपनी अंदरूनी खींचतान पर ध्यान दे

कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की चिंता छोड़े,केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भड़के

रायपुर,25 जून 2026। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि, भाजपा को कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की चिंता छोड़ अपनी सरकार और संगठन की अंदरूनी खींचतान पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। नए जिला अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि, राहुल गांधी की सोच के अनुरूप कांग्रेस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के अभियान में जुटी है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम देश के कई राज्यों में सफलतापूर्वक आयोजित किए जा रहे हैं। जिनमें राजनीतिक, सामाजिक और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कथित झूठे वादों,नीतियों और जनविरोधी फैसलों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति भी बनाई जा रही है।

राम मंदिर दान में गड़बड़ी गंभीर : पायलट

राम मंदिर निर्माण के लिए मिले दान में कथित गड़बड़ी और करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोपों पर पायलट ने कहा कि,मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोषी चाहे किसी भी दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक इस मामले में कोई जांच नहीं कराई है,जबकि भाजपा भगवान के नाम पर राजनीति करती है लेकिन आरोपों पर जवाब देने से बच रही है।

सीएम यादव पर साधा निशाना

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिजनों के नाम कथित जमीन खरीद मामले में पायलट ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार और नैतिकता के मामलों में दोहरे मापदंड अपनाती है। 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' का दावा करने वाली भाजपा को आरोपों पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भड़के

सचिन पायलट ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि, विपक्षी नेताओं को सीबीआई और ईडी के जरिए निशाना बनाया जाता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता जरूरी है। अंततः सत्य और जनता की आवाज की ही जीत होगी।

छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा के लिए बड़ा कदम...सभी बसों में ट्रैकिंग डिवाइस को किया गया अनिवार्य,उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर,25 जून 2026। छत्तीसगढ़ में यात्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी यात्री बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) लगाना और उसे सक्रिय रखना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियम का पालन नहीं करने वाले बस संचालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम,1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव एवं परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने आज इंद्रावती भवन, नवा रायपुर स्थित परिवहन कार्यालय में सभी बस संचालकों एवं विभाग द्वारा वीएलटीडी लगाने के लिए अधिकृत वेंडरों की संयुक्त बैठक लेकर यात्री बसों में स्थापित वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि जिन बसों में अभी तक वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) नहीं लगी है, उनमें 15 दिनों के भीतर इसे अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाए। वहीं जिन बसों में यह उपकरण लगा हुआ है लेकिन संचालित नहीं है, उन्हें तत्काल चालू किया जाए।

सड़क हादसों के बाद लिया गया निर्णय : परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में राजस्थान के फलोदी और तेलंगाना के रंगारेड्डी में हुए भीषण सड़क हादसों के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है। सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाली महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।

कमांड सेंटर से होगी निगरानी : विभाग ने बताया कि राज्य मुख्यालय के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से सभी बसों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उपग्रह आधारित ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि बस निर्धारित मार्ग पर चल रही है या नहीं तथा समय पर संचालन हो रहा है या नहीं। यात्रियों को भी संगवारी ऐप के जरिए बसों की वास्तविक समय की लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी।

तकनीकी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है : अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे और बुद्धिमान यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की जा रही है। इससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की तत्काल पहचान कर कार्रवाई की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एक उपग्रह आधारित प्रणाली है, जो वाहन की हर पल की स्थिति और लोकेशन की जानकारी नियंत्रण केंद्र तक पहुंचाती है।

कबीरधाम में 5.5 किलो गांजा बरामद,एक तस्कर गिरफ्तार,3.52 लाख रुपए का गांजा

कबीरधाम,25 जून 2026। कबीरधाम पुलिस ने जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 किलो 579 ग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना पिपरिया और साइबर थाना कबीरधाम की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई करते हुए करीब 3 लाख 52 हजार रुपये मूल्य का मादक पदार्थ, बाइक और मोबाइल जब्त किया है। पुलिस के अनुसार, 24 जून को थाना पिपरिया को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पिपरिया और साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई।

भारत माता चौक में घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी : पुलिस टीम ने भारत माता चौक पिपरिया में घेराबंदी कर संदिग्ध बाइक सवार को रोककर पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना नाम हुकमी चंद चंद्रवंशी निवासी ग्राम कान्हाभैरा बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 5 किलो 579 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

गांजा,बाइक और मोबाइल जब्त : कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी से 2 लाख 75 हजार रुपये मूल्य का गांजा, 65 हजार रुपये की मोटरसाइकिल और 12 हजार रुपये का मोबाइल फोन जब्त किया। कुल जब्ती की कीमत लगभग 3 लाख 52 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी हुकमी चंद चंद्रवंशी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)